



राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम

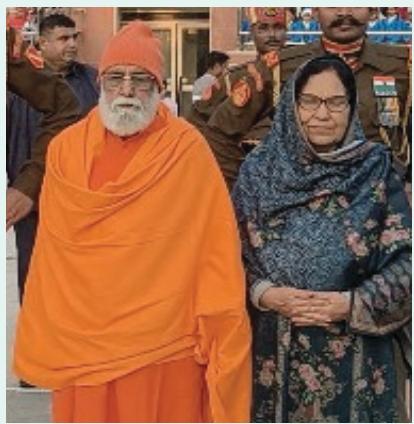
भारत श्री

राष्ट्रीय हिंदी साप्ताहिक

सोमवार, 08 दिसंबर 2025 ● वर्ष 7 ● अंक 21 ● मूल्य: 5 रुपए

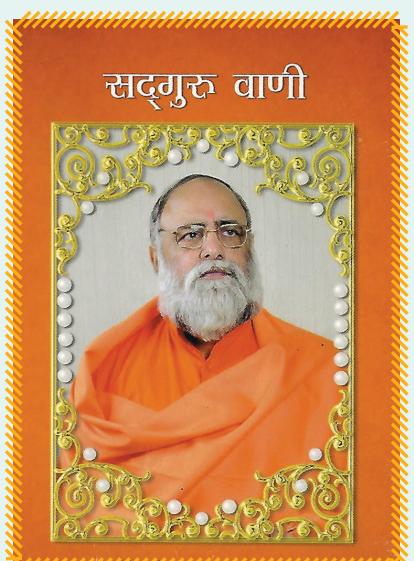


काम के बाद भी काम का बोझ



भारत-पाक सीमा फिरोजपुर पर
जगदुरु महाब्रह्मत्रैषि श्री कुमार
स्वामी जी का आगमन, गुरु माँ
भी रहीं साथ

पेज-10-11



विश्व भर में होने वाले प्रभु कृपा दुख निवारण
समागम केवल प्रभु की कृपा से संभव होते हैं।
इसका आयोजन कोई व्यक्ति नहीं करता।

परमात्मा की नजर में सभी भाई-बहन बराबर हैं। परमात्मा जाति, धर्म, देश, सम्प्रदाय से पार है। हमें सभी भाई-बहनों को समान दृष्टि से देखना चाहिए।

दिव्य पाठ प्रभु कृपा का वह आलोक है जिसे करने के लिए किसी भी प्रकार की कठिन तपस्या या साधना की कोई जरूरत नहीं है। यह बड़ा सहज और सरल है।

वंदे मातरम् के 150 साल वन्दे मातरम्

संसद में
गूंजा गीत,
राजनीति में
तेज हुई गर्मी

राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष का स्मरणोत्सव



मुख्य अनिधि

नरेन्द्र मोदी

मा



ORDER ALL TYPES OF :

- POOJA SAMAGRI,
- AYURVEDIC MEDICINE
- AND PRATIMA.



NOW GET AT YOUR HOME ON
MNDIVINE.COM



ORDER NOW



<https://mndivine.com/>

HELPLINE : 9667793986
(10AM TO 6PM, MON-SAT)



साफ हवा ने दिल्ली को नया आईना दिखाया



वापसी का पहला झटका: प्रदूषण की अनकही सच्चाई

दि

ल्ली लौटने पर पहली सांस ही किसी को हिला कृशवाहा की कहानी कुछ ऐसी ही है। वे दिल्ली छोड़कर दूसरे शहरों में बसे, जहां हवा साफ थी और सांस लेना आसान। लेकिन दिसंबर 2025 में जब वे एयरपोर्ट पर उतरे, तो बस पांच सेकंड में खांसी शुरू हो गई। हवा की गंध ही बता रही थी कि कुछ गडबड है। पहले तो वे सोचते थे कि दिल्ली की धूंध को वे सह लेते हैं, लेकिन अब लगता है कि यह शहर की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, मौसम का नाम नहीं। कुणाल कहते हैं कि पहले वे धूंध को नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन अब समझ आया कि यह सामान्य नहीं। दिल्ली की हवा अब साल भर खराब रहती है, सिर्फ सर्दियों तक सीमित नहीं। 2025 में जनवरी से नवंबर तक औसत AQI 187 रहा, जो 2024 के 201 से बेहतर है। लेकिन दिसंबर आते ही यह 333 पर पहुंच गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। यह आंकड़ा बताता है कि सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी लंबा रास्ता बाकी। कुणाल की तरह कई दिल्लीवासी अब महसूस कर रहे हैं कि प्रदूषण सिर्फ सांस की समस्या नहीं, बल्कि शहर की पहचान बदल रहा है। वे सोचते हैं कि दिल्ली की तेज रफ्तार, ट्रैफिक और निर्माण कैसे हवा को जहर बना देते हैं। लेकिन इस झटके ने उन्हें यह भी सिखाया कि शहर की ताकत उसकी सहनशीलता में है। लोग यहां रहते हैं, लड़ते हैं, लेकिन अब सवाल उठता है कि कब तक? विशेषज्ञ कहते हैं कि PM2.5 कण फेफड़ों के अलावा दिमाग तक पहुंच जाते हैं, जो लंबे समय में बीमारियां बढ़ाते हैं। कुणाल की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि साफ हवा न सांस लेने का अधिकार है, बल्कि शहर को समझने का नजरिया भी। यह वापसी सिर्फ हवाई जहाज से नहीं, बल्कि अपनी जड़ों से हुई। दिल्ली अब सिर्फ घर नहीं, एक सबक है। यहां की हवा हमें बताती है कि विकास के नाम पर क्या खो रहे हैं। लेकिन उम्मीद भी जगाती है, क्योंकि 2025 में अच्छे

शहर की सांसोंमें सुधार: छोटे कदमों की बड़ी जीत

2025 दिल्ली के लिए प्रदूषण के रिवाफ एक नई शुरुआत जैसा रहा। साल भर में अच्छे हवा के दिन 100 हो गए, जो 2016 के 110 से दोगुने हैं। यह बदलाव सरकार की कोशिशों से आया — जैसे वाहनों पर सख्ती, फसल जलाने पर याचिंटी और सार्वजनिक बसों बढ़ाना। जनवरी से नवंबर तक AQI 187 रहा, जो पिछले सालों से बेहतर। लेकिन दिसंबर में फिर घूनौती — AQI 333, धूंध की चादर। दिल्लीवासियों की कलहियां बताती हैं कि ये सुधार महसूस हो रहे हैं। एक कैफे मालिक ने बताया कि लोग अब हरे-भरे इलाकों में आते हैं, साफ हवा के लिए। साफ हवा ने सिखाया कि शहर बदल सकता है, अगर सब भिलकर कोशिश करें। एक डॉक्टर ने 40 साल के अनुभव से कहा कि प्रदूषण को सामान्य न मानें, साफ हवा रोज का छक है। बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित, लेकिन सुधार से उनकी सेवत बेलतर हो सकती है। एक फाउंडेशन ने शेयर किया कि दिल्ली आकर सिरदर्द और आंखों में जलन रुई, लेकिन साल के अच्छे दिनों ने उम्मीद दी। यह सबक है कि प्रदूषण सिर्फ समस्या नहीं, अवसर भी। शहर की भौगोलिक स्थिति — पठाड़ों से घिरी घाटी — प्रदूषकों को फंसा लेती है, लेकिन मानवीय प्रयास इसे रुक सकते हैं। दिल्लीवासी अब समझते हैं कि उनकी आदतें — कार यूलिंग, कवरा अलग करना — हवा बदल सकती हैं। सुधार ने शहर को आईना दिखाया कि वह सिर्फ राजधानी नहीं, बल्कि सांसों का शहर है। लेकिन घूनौतीयां बाकी, जैसे वाहनों का धुआं और धूल। अगर ये कदम जारी रहे, तो 2030 तक बड़ा फर्क पड़ सकता है। यह परिवर्तन व्यक्तिगत स्तर पर भी दिखता है — लोग अब मारक यहनते हैं, घरों में व्यूरीफायर लगाते हैं। साफ हवा की झलक ने दिल्ली को व्यारा बनाया, और सोचाया कि इसे लम्शा के लिए कैसे रखें।

दिन बढ़े हैं — 200 दिन AQI 200 से नीचे रहा। यह बदलाव छोटे कदमों से आया, जैसे सार्वजनिक परिवहन बढ़ाना और फसल जलाने पर रोक। कुणाल अब सोचते हैं कि अगर वे बदल सकते हैं, तो शहर क्यों नहीं? यह व्यक्तिगत अनुभव शहर की व्यापक तस्वीर खोलता है, जहां हर सांस एक याद दिलाती है कि दिल्ली को बचाना हमारी जिम्मेदारी है।

साफ हवा की ताजगी: दूरियों से आई नई नजर

जब कोई दिल्लीवासी दूसरे शहर चला जाता है, तो पहली चीज जो महसूस होती है, वह है सांसों की आजादी। कुणाल की तरह कई लोग बताते हैं कि साफ हवा ने उन्हें

जरूरत पड़ी, सिर्फ दो साल दिल्ली रहने से। यह कहानियां बताती हैं कि साफ हवा दूर जाकर मिली, लेकिन दिल्ली के बारे में सोच बदल गई। लोग अब देखते हैं कि शहर की खूबसूरती — पुरानी इमारतें, बाजार, पार्क — प्रदूषण के नीचे दब रही हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषक फेफड़ों को चुपचाप नुकसान पहुंचाते हैं, खांसी और सांस की तकलीफ बढ़ाते हैं। लेकिन इस दूरी ने एक सबक दिया — दिल्ली की ताकत उसके लोगों में है। वे मुश्किलों में भी हंसते हैं, लेकिन अब बदलाव की मांग कर रहे हैं। एक उद्यमी ने लिखा कि अपनी बेटी के लिए NCR छोड़ने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि रातों में खांसी सताती है। साफ हवा ने सिखाया कि शहर सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि सांसें हैं।

प्रदूषण के सबक: शहर की छिपी ताकतें

साफ हवा का अनुभव दिल्ली को नया रूप देता है, जहां प्रदूषण के बीच शहर की असली ताकत झलकती है। कुणाल जैसे लोग बताते हैं कि धूंध ने सहनशक्ति सिखाई, लेकिन साफ हवा ने दिखाया कि जिंदगी इससे ज्यादा हो सकती है। 2016 की एक पुरानी कहानी में किसी ने लिखा कि दिल्ली में घर के अंदर ही ताजी हवा मिलती है, लेकिन अब 2025 में सुधार से लोग बाहर निकलने लगे। शहर की विविधता — गलियां, बाजार, पार्क — प्रदूषण के बावजूद जीवंत रहती है। एक रिपोर्ट कहती है कि सड़कों की धूल सबसे बड़ा प्रदूषक है, जो पैदल चलना मुश्किल बनाती है। लेकिन इससे सीख मिलती है कि साफ सड़कों शहर को सम्मान देंगी। दिल्लीवासी अब समझते हैं कि प्रदूषण आर्थिक नुकसान भी पहुंचाता है — पर्यटन घटता है, स्वास्थ्य खर्च बढ़ता है। एक मां की पोस्ट ने बताया कि बच्चे के स्वास्थ्य के लिए शहर छोड़ना पड़ा, जो सबके लिए चेतावनी है। साफ हवा ने सिखाया कि दिल्ली की संस्कृति — त्योहार, भोजन, बातें — साफ पर्यावरण में और चमकदार हो सकती हैं। विशेषज्ञ चेताते हैं कि लंबे समय का प्रदूषण कैसर और कमज़ोर इम्प्रूनिटी लाता है।

नई इयूटी नियमों की चोट इंडिगो की उड़ानें क्यों ठप हो गईं?

भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो इन दिनों मुश्किलों के घेरे में है। दिसंबर 2025 की शुरुआत में ही कंपनी ने पूरे देश में सेकड़ों उड़ानें रद्द कर दीं, जिससे लाखों यात्री परेशान हो गए। 5 दिसंबर को अकेले 1000 से ज्यादा उड़ानें कैसल हुईं, और 6 दिसंबर को भी सेकड़ों की संख्या में रद्दीकरण जारी रहा। दिल्ली, मुंबई, बैंगलुरु और हैदराबाद जैसे बड़े हवाई अड्डों पर सुबह से शाम तक अफरा-तफरी मच गई। यात्री घंटों इंतजार करते रहे, फिर भी उनकी उड़ानें कैसल हो गईं। कई लोग रात भर एयरपोर्ट पर फंसे रहे, भूखे-प्यासे परेशान हुए। एक तरफ बुजुर्ग और बच्चे रोते नजर आए, तो दूसरी तरफ गुस्से में लोग एयरलाइन स्टाफ पर चिल्लाए। यह सब कुछ नई फ्लाइट इयूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों की वजह से हुआ, जो पायलटों की थकान कम करने के लिए लाए गए थे। लेकिन इन नियमों ने इंडिगो की सारी प्लानिंग को उलट-पुलट कर दिया। कंपनी रोजाना 2200 उड़ानें चलाती है, जो भारत की कुल हवाई यात्रा का 63 फीसदी है। इतनी बड़ी स्केल पर कोई छोटी सी दिक्कत भी पहाड़ बन जाती है। विंटर शेड्यूल शुरू होते ही यह समस्या और गंभीर हो गई, क्योंकि छुट्टियों के मौसम में यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। इंडिगो ने कहा कि यह कई ऑपरेशनल दिक्कतों का नतीजा है, लेकिन मुख्य वजह ये नए नियम ही हैं। यात्री अब ट्रेनों की ओर रुख कर रहे हैं, और दूसरी एयरलाइंप जैसे स्पाइसजेट ने अतिरिक्त उड़ानें शुरू कीं। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी कंपनी इतनी जल्दी कैसे फंस गई? यह घटना न सिर्फ इंडिगो बल्कि पूरे हवाई उद्योग को सोचने पर मजबूर कर रही है। क्या सुरक्षा के नाम पर यात्री सुविधा दांव पर लग गई? सरकार ने तुरंत कदम उठाए, लेकिन नुकसान तो हो चुका है।

नए नियमों का दम-खम: पायलटों की थकान पर लगाम

DGCA यानी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने नवंबर 2025 से नए फ्लाइट इयूटी टाइम लिमिटेशन नियम लागू किए, जो वैश्विक मानकों के हिसाब से पायलटों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए हैं। पहले के नियमों में पायलटों को हफ्ते में 36 घंटे आराम मिलता था, लेकिन अब यह 48 घंटे हो गया है। यानी हर हफ्ते दो अतिरिक्त दिन की छुट्टी। इसके अलावा, रात की उड़ानों पर सख्त पांचदंशी लगाई गई। पहले एक पायलट हफ्ते में 6 रात लैंडिंग कर सकता था, लेकिन अब सिर्फ 2। रात की उड़ानों अब 8 घंटे तक सीमित हैं, और इयूटी के बाद आराम इयूटी की लंबाई से दोगुना होना चाहिए, कम से कम 10 घंटे हर 24 घंटे में। रोजाना फ्लाइट टाइम 8 घंटे, हफ्ते में 35, महीने में 125 और साल में 1000 घंटे तक ही। ये बदलाव थकान से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हैं, क्योंकि लंबी इयूटी से पायलटों की एकाग्रता कम हो जाती है। पुराने नियमों में ज्यादा लचीलापन था, कंपनियां आसानी से शेड्यूल बना



लेती थीं। लेकिन नए नियमों ने रोटेशन को कड़ा कर दिया। अब एक प्लेन के लिए ज्यादा पायलट चाहिए, क्योंकि रेस्ट पीरियड बढ़ गए। रात की लंबी विंडो भी बढ़ा दी गई, जिससे उड़ानें कम हो सकती हैं। DGCA का कहना है कि यह सब सुरक्षा के लिए जरूरी है, और दुनिया के दूसरे देशों में भी ऐसे ही नियम हैं। लेकिन समस्या यह है कि एयरलाइंस को इनके लिए तैयार होने का पूरा समय नहीं मिला। विंटर शेड्यूल को मंजूरी देते वक्त DGCA ने पायलटों की उपलब्धता चेक करनी चाहीए। नतीजा, अचानक लागू होने पर हड्डबड़ी मच गई। पायलट यूनियंस का आरोप है कि कंपनियां पहले से ही कम स्टाफ रखती हैं, और हायरिंग फ्रीज ने हालात बिगड़ा दिए। ये नियम अच्छे हैं, लेकिन अमल में आने का तरीका सोचने लायक है। क्या जल्दबाजी ने फायदे की बजाय नुकसान पहुंचाया?

इंडिगो की कमज़ोरी उजागर: तेयारी में छूक

इंडिगो पर इन नए नियमों की मार सबसे ज्यादा क्यों पड़ी, इसका जवाब कंपनी की अपनी कमियों में लिपा है। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन होने के नाते इंडिगो का नेटवर्क घना है, रोज 2200 उड़ानें और रात की फ्लाइट्स की भरमार। नए नियमों ने रात लैंडिंग सीमित कर दी, जिससे उनके शेड्यूल का बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ। कंपनी के पास 5500 पायलट हैं, लेकिन नए नियमों के तहत 1100 और चाहिए, जिनमें 200 फरवरी 2026 तक चलेंगी। यह छूट सिर्फ ऑपरेशंस इंस्पेक्टर्स द्वारा करने के लिए है, सेफ्टी पर कोई समझौता नहीं। DGCA ने इंडिगो को फ्लाइट ऑपरेशंस स्टेबलाइज करने के लिए दिए हैं, जो मालिनिंग में मदद करेंगे। सिविल एविएशन मिनिस्टर ने पायलट बॉडी से बात की, और सहयोग मांगा। यात्री सुविधाओं के लिए सख्त निर्देश दिए: कैसल उड़ानों पर फुल रिफंड,

लंबी देरी पर होटल, सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों को लाउंज एक्सेस, रिफ्रेशमेंट्स। एयरलाइंस को रीयल-टाइम अपडेट ऑनलाइन डालने को कहा। एक हाई-लेवल जांच कमिटी बनी, जो रद्दीकरण की वजहें, जिम्मेदारी और भविष्य के उपाय सुझाएंगी। इंडिगो ने कहा कि ऑपरेशंस धीरे-धीरे पटरी पर आ रहे हैं, और 8 दिसंबर तक नॉर्मल हो जाएंगा। लेकिन 400 उड़ानें छूट के बाद भी कैसल हुईं, जो दिखाता है कि समस्या गहरी है। सरकार ने एयरफेयर कैप लगाए, ताकि टिकट महंगे न हों। यह प्रतिक्रिया सराहनीय है, लेकिन सवाल उठता है कि फहले क्यों नहीं रोका गया? DGCA का रोल भी जांच का विषय बनेगा। कुल मिलाकर, यह कदम यात्रियों को राहत देंगे, लेकिन विश्वास बहाल करने में वक्त लगेगा।

भविष्य की सीख: यात्री दर्द और उद्योग सुधार

यह संकट यात्रियों के लिए सबक है कि हवाई सफर में अनिश्चितता रहती है, खासकर बड़े बदलावों के समय। हजारों लोग फंसे गए, कामकाज प्रभावित हुआ, छुट्टियां बर्बाद। लेकिन सकारात्मक पक्ष यह है कि सुरक्षा पर जोर बढ़ा। नए नियम थकान कम करेंगे, दुर्घटनाएं घटेंगी। इंडिगो को अब पायलट हायरिंग तेज करनी होगी, ट्रेनिंग बढ़ानी होगी। पूरे उद्योग को रोस्टर प्लानिंग में स्मार्ट बनाना पड़ेगा। DGCA को भविष्य में शेड्यूल मंजूरी सख्त करनी चाहिए। पायलट यूनियंस और मैनेजमेंट के बीच बातचीत जरूरी, ताकि हायरिंग फ्रीज जैसी गलतियां न हों। यात्री सलाह: हमेशा अल्टरनेटिव प्लान रखें, जैसे ट्रेन बुकिंग। लंबे में, यह घटना हवाई यात्रा को मजबूत बनाएंगी। क्या हम बेहतर सिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं? हां, लेकिन कीमत यात्रियों ने चुकाई। उम्मीद है कि अगली बार ऐसी हड्डबड़ी न हो।

भारत-रूस दोस्ती की नई ऊंचाई पुतिन की दिल्ली यात्रा ने दिल जीता

रूस

सी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दो दिवसीय भारत यात्रा 4 दिसंबर 2025 को शुरू हुई, जब वे दिल्ली पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उनका स्वागत किया, जो आम तौर पर प्रोटोकॉल से अलग था। दोनों नेताओं ने गले मिलकर हंसी-मजाक किया और एक ही कार में सवार होकर लोक कल्याण मार्ग पर निजी डिनर के लिए रवाना हो गए। यह पल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जहां मोदी ने लिखा कि वे अपने दोस्त पुतिन का स्वागत करने को उत्साहित हैं। अगले दिन, 5 दिसंबर को राष्ट्रपति भवन में औपचारिक समारोह हुआ। राष्ट्रपति द्वापदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। फिर 21 तोपों की सलामी गूंजी, जो भारत की परंपरा के मुताबिक किसी बड़े मेहमान के सम्मान में दी जाती है। यह दृश्य पुरानी इमारत के आंगन में शानदार लगा, जहां भारतीय सेना के जवानों ने फरेड की। पुतिन ने कहा कि यह स्वागत उनकी दोस्ती का प्रतीक है। इस समारोह के बाद दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल ने द्विपक्षीय वार्ता की, जो 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का हिस्सा था। यात्रा का यह शुरुआती हिस्सा न सिर्फ औपचारिक था, बल्कि गर्मजौशी भरा भी। पुतिन की यह पहली यात्रा 2022 के यूक्रेन संकट के बाद की है, इसलिए यह कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनी। अमेरिकी दबाव के बीच भारत ने रूस को महत्व दिया, जो ऊर्जा और रक्षा में पार्टनर है। यह स्वागत दर्शाता है कि दोनों देश अपनी साझेदारी को मजबूत रखना चाहते हैं, भले ही वैश्विक तनाव हो। शाम को बैनक्वेट डिनर हुआ, जहां दोनों ने व्यापार और सहयोग पर बात की। कुल मिलाकर, यह स्वागत भारत की मेजबानी की मिसाल बना, जो पुरानी दोस्ती को नया रंग दे रहा था। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह यात्रा सिर्फ समारोहों तक सीमित रहेगी या वास्तविक बदलाव लाएगी?

राजघाट पर गांधी को नमन और गीता का प्यारा तोहफा

पुतिन की यात्रा का एक भावुक पल था राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देना। सुबह के समय पुतिन गांधीजी के समाधि स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने फूलमाला चढ़ाई और मौन रखा। उसके बाद विजिटर्स बुक में हस्ताक्षर किए। पुतिन ने लिखा कि गांधी आधुनिक भारत के संस्थापक हैं और न्याय व अहिंसा के वैश्विक प्रतीक। उन्होंने कहा, “गांधी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा हैं, उनकी विचारधारा आज भी दुनिया को रास्ता दिखाती है।” यह शब्द रूसी-अंग्रेजी में लिखे गए, जो गांधी की वैश्विक अपील को दर्शाते हैं। पुतिन के साथ भारतीय अधिकारी थे, और पूरा समारोह शांतिपूर्ण रहा। गांधी की अहिंसा रूस के शांति प्रयासों से जुड़ती दिखी, खासकर यूक्रेन संदर्भ में। इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को रूसी भाषा में अनुवादित भगवद्गीता की प्रति भेंट की। मोदी ने कहा, “गीता के उपदेश दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। यह किताब जीवन के रहस्य सिखाती है।”

शिखर सम्मेलन की चमकदार झलकियां और पुतिन के दिल छोड़ने वाले बयान

23वें भारत-रूस शिखर सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण पल हुए, जो दोनों देशों के सहयोग को नई दिशा दे रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में वार्ता के बाद पुतिन और मोदी ने संयुक्त संप्रेस कॉन्फ्रेंस की। पुतिन ने कहा कि रूस भारत को “बिना रुके ईंधन आपूर्ति” देगा, जिसमें तेल, गैस और कोयला शामिल है। उन्होंने जोर दिया, “हम विश्वसनीय सप्लायर हैं, अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद हमारा बाद अटल है।” यह बयान भारत की ऊर्जा जरूरतों को ध्यान

में रखकर था, क्योंकि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदता है। पुतिन ने यूक्रेन मुद्दे पर अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि शांति संवाद से ही संभव है, और भारत जैसे दोस्तों की भूमिका अहम है। मोदी ने जवाब में कहा कि रूस-भारत दोस्ती “धूम तारा” जैसी है, जो कभी नहीं बदलती। सम्मेलन में बिजनेस फोरम भी हुआ, जहां व्यापारियों ने विचार साझा किए। एक मजेदार पल था जब पुतिन और मोदी ने कार शेयर की, जो उनकी नजदीकी दिखाता है। शाम को बैनक्वेट डिनर में दोनों ने स्वास्थ्य और नौकरियों पर बात की। पुतिन के अन्य बयान में रक्षा सहयोग पर जोर था, जहां उन्होंने कहा कि रूस भारत की “आत्मनिर्भरता” में मदद करेगा। उन्होंने गांधी पर फिर कहा कि उनकी अहिंसा आज के संघर्षों के लिए सबक है। ये बयान न सिर्फ कूटनीतिक थे, बल्कि विचारोत्तेजक भी, क्योंकि वे पश्चिमी दबाव के बीच रूस की स्थिति स्पष्ट करते हैं। भारत ने संतुलन बनाए रखा, न तो रूस की निंदा की न ही अमेरिका को नाराज किया। सम्मेलन की झलकियां दर्शाती हैं कि यह यात्रा सिर्फ औपचारिकताएं नहीं, बल्कि वास्तविक साझेदारी है। लेकिन क्या ये बयान अमल में बदलेंगे, यह समय बताएगा। कुल मिलाकर, यह दिन ऊर्जा, शांति और दोस्ती के संदर्भों से भरा रहा।

नए समझौते की बाद और दोनों देशों के रिश्तों पर दूरगामी प्रभाव

शिखर सम्मेलन में 10 से ज्यादा अंतर-सरकारी समझौते और 15 वाणिज्यिक एमओयू साइन हुए, जो



मीडिया का व्यवसाय

मीडिया पूरी तरह व्यापार है व्यापारिक तरीके से गीत कार्य करता है। मीडिया व्यावसायिक तरीके से शूब्य को असीमित भी बना सकता है और वह इतनी भी ताकत रखता है की असीमित को शूब्य स्थापित कर दे। मीडिया की शक्ति से आगतौर पर सब लोग प्रभावित रहते हैं लेकिन संघ ने कभी मीडिया का सहारा नहीं लिया यही कारण है कि संघ को स्थापित होने में बहुत अधिक समय लगा और विरोध करने के बाद भी मीडिया संघ को कमज़ोर नहीं कर सका। मैंने भी बचपन से मीडिया से दूरी बनाकर रखी व्योंग में मीडिया की शक्ति को समझता था। लेकिन यह बात भी सच है कि यह बहुत देर से ही क्यों ना हो सच सामने आता ही है। यह बात सच है कि भारत के नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ से ही विस्तार और चुनौती निली। छत्तीसगढ़ के विस्तार में राजनेता दिग्विजय सिंह और गांधीवादी ब्रह्मदेव शर्मा का बहुत बड़ा योगदान रहा और समापन में भी गांधीवादी ठाकुरदास बंग तथा मेरा बहुत योगदान रहा। नक्सलवाद के विस्तार की रूपरेखा बस्तर से लिखी गई और समापन की रूपरेखा रामानुजगंज में लिखी गई। विस्तार के लिए व्यवस्था परिवर्तन नारा दिया गया और समापन के लिए लोक स्वराज का नारा दिया गया। लेकिन मीडिया के सलारे विस्तार की योजनाएं तो दुनिया को पता चलती रही लेकिन मीडिया से किनारे होने के कारण रामानुजगंज से समापन की योजना समाज के सामने नहीं आ सकी। लेकिन जैसा कि देर होने के बाद भी सच सामने आता ही है एक राष्ट्रीय समाचार एजेंसी हिंदुस्तान समाचार के युग वार्ता संस्करण में रामानुजगंज से नक्सलवाद के समापन की शुरुआत पर कुछ प्रकाश डाला गया है। शुरुआत बहुत अच्छी है सच धीरे-धीरे सामने आएगा। हम इस खोज के लिए युग वार्ता और हिंदुस्तान समाचार को ध्वन्यवाद देते हैं।

बजरंग मुनि

जुबानी तीर

“

कांग्रेस ने 1937 में वंदे मातरम् को काटकर इसकी मूल भावना कमज़ोर की, वंदे मातरम् आजादी की आत्मा है, इस गीत ने देश को एक जुट किया और इसे सम्मान मिलना ही चाहिए।



नरेंद्र मोदी (प्रधानमंत्री)

“

भाजपा इतिहास को तोड़-मरोड़ रही है, वंदे मातरम् पर बहस को राजनीतिक हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए, यह गीत हमारे लिए भी उतना ही पवित्र है।



जयराम रमेश (कांग्रेस)

“

वंदे मातरम् हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, कांग्रेस ने कभी इसके सम्मान को कम नहीं किया, सरकार इसे विभाजन की राजनीति का मुद्दा न बनाए।



प्रियंका गांधी (कांग्रेस)

“

किसी को वंदे मातरम् गाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, राष्ट्रीय एकता का अर्थ सभी समुदायों की भावनाओं का सम्मान करना है, किसी गीत को पहचान की परीक्षा नहीं बनाया जाना चाहिए।



असदुद्दीन ओवैसी (AIMIM)

राष्ट्रीय आत्मा की कस्तूरी

@ अनुराग पाठक

सं

सद में वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने पर हुई चर्चा को केवल एक सांस्कृतिक स्मरण के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए। यह बहस उसी भारत की राजनीतिक, वैचारिक और सामाजिक हलचलों का दर्पण है, जिसने अपने अस्तित्व को बार-बार परिभाषित करने का साहस दिखाया है। वंदे मातरम् कोई साधारण गीत नहीं, यह वह विंब है जिसे हर दौर ने अपने हिसाब से नया अर्थ दिया है। आज संसद में उठी आवाजें बता रही हैं कि 150 साल बाद भी यह गीत भारतीय चेतना की कसौटी है। जहाँ राजनीति, संस्कृति और इतिहास एक-दूसरे से टकराते भी हैं और एक-दूसरे को नया आकार भी देते हैं।

वंदे मातरम् की यात्रा बंकिम चंद्र चटर्जी की निजी संवेदना से शुरू होती है, पर उसकी मंजिल एक राष्ट्र की सामूहिक चेतना है। आनंदमठ में बंकिम ने भारत को मां दुर्गा के रूप में देखा यह सिर्फ धार्मिक कल्पना नहीं थी, बल्कि उस समय के भारतीय मन की बेचैनी का चित्रण था। गुलाम भारत किसी राजनीतिक कारण से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के अपमान से त्रस्त था। ऐसे में वंदे मातरम् मातृभूमि के प्रति श्रद्धा का गीत नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की पुनर्प्राप्ति का उद्घोष बन गया। सवाल है कि क्या यह भाव आज भी उतनी ही ताकत से मौजूद है? संसद की बहस में दो ध्रुव स्पष्ट दिखे—एक पक्ष इसे अधूरे रूप में गाए जाने को ऐतिहासिक भूल मानता है, तो दूसरा पक्ष कहता है कि गीत का पूर्ण पाठ विविध भारत की भावनाओं से मेल नहीं खाता। लेकिन असल प्रश्न यह नहीं कि कब क्या हाताया गया, असल प्रश्न यह है कि आज के भारत में वंदे मातरम् का अर्थ क्या है? क्या यह गीत हमें जोड़ने की एक सांस्कृतिक डोर है या राजनीतिक बहसें इसे अलग-अलग खेमों में बाँट रही हैं?

यह सही है कि 1930 के दशक में गीत को लेकर धार्मिक आपत्तियाँ उठीं। लेकिन इन आपत्तियों में केवल धार्मिक असहजता नहीं थी, बल्कि उभरते भारत की पहचान का सवाल भी छिपा था। क्या भारत की राष्ट्रीय पहचान पूजा के प्रतीकों से बनेगी या उस भूमि के प्रति समर्पण से जो हम सबकी साज्जा है? यही दुविधा है जिसे आज भी सार्थक ढंग से हल नहीं किया गया है। सरकारें बदलती रहीं, लेकिन वंदे मातरम् का अर्थ हर सत्ता ने अपने तरीके से गढ़ने की कोशिश की।

तथ्य यह है कि वंदे मातरम् ने देश की आजादी में जितनी प्रेरणा दी, उतनी किसी अन्य गीत ने नहीं। इसके शब्दों में वह ऊर्जा है जिसने आंदोलनों को गति दी, जिसने युवाओं के भीतर साहस जगाया। लेकिन यह भी सच है कि आज की राजनीति इस गीत को प्रेरणा के बजाय आरोप-प्रत्यारोप का हथियार बनाने लगी है।

यह प्रवृत्ति चिंताजनक है, क्योंकि इससे वंदे मातरम् का मूल अर्थ एकता—कमज़ोर होता है। वंदे मातरम् का सबसे बड़ा महत्व इस बात में नहीं है कि इसमें कौन-सा शब्द कहाँ आया है। इसका महत्व उस भाव में है जो यह देशवासियों के भीतर जगाता है। यह गीत मातृभूमि की निष्ठा और स्वतंत्रता की आकंक्षा का प्रतीक है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में इसे धार्मिक पहचान के चश्मे से देखने की आदत पड़ गई है, जिससे इसका सारा धीरे-धीरे धूमिल होता गया।

आज भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ वह वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में सांस्कृतिक प्रतीकों को लेकर असुरक्षा या संघर्ष का वातावरण हमारे राष्ट्रीय आत्मविश्वास को कमज़ोर करता है। वंदे मातरम् को 150 साल बाद उसी ऊर्जा से याद करने की आवश्यकता इसलिए है, क्योंकि यह गीत हमें यह याद दिलाता है कि राष्ट्र की पहचान किसी एक पंथ या समूह से नहीं, बल्कि उस सामूहिक भावना से बनती है जो कष्ट सहकर भी अपने भविष्य को बेहतर बनाने का साहस रखती है।

यह भी ज़रूरी है कि हम वंदे मातरम् को केवल इतिहास की कसौटी पर न तौलें। इसे वर्तमान के संदर्भ में समझना होगा। एक युवा जब वंदे मातरम् सुनता है, तो उसके मन में यह गीत कितनी अर्थपूर्ण जगह धेरता है? क्या यह गीत उसके भीतर वही भाव जगाता है जो स्वतंत्रता सेनानियों के भीतर जगता था? या यह गीत आज केवल राजनीतिक विवादों में उलझा एक प्रतीक बनकर रह गया है? यही प्रश्न है जिसका उत्तर 150 वर्षों के इस अवसर पर खोजा जाना चाहिए। संसद में बहस जरूरी है, लेकिन बहस को सार्थक दिशा भी चाहिए। यह चर्चा अगर एक-दूसरे पर आरोप लगाने की जगह उस विचार को मजबूत करे कि एक राष्ट्र अपनी विविधता के साथ भी कैसे एक भाव में बंध सकता है, तो वंदे मातरम् के 150 वर्ष मनाना साथक होगा। दिल्ली की संसद से लेकर गांव की पाठशाला तक, वंदे मातरम् का अर्थ उतना ही जीवंत होना चाहिए जितना बंकिम ने महसूस किया था। एक ऐसा देश जो अपनी धरती को मां मानता है, लेकिन सभी पुत्रों को बराबरी का स्थान भी देता है।

वंदे मातरम् का वास्तविक महत्व उस क्षण में है जब कोई भारतीय पहली बार इसे समझता और महसूस करता है। वह क्षण किसी पूजा का नहीं, बल्कि पहचान का होता है। यही इस गीत की शक्ति है, और यही उसका भविष्य भी। अगर हम इसे विवादों से मुक्त कर पुनः उस भाव की ओर लौटें जो इस गीत की आत्मा है, तब हम कह पाएंगे कि 150 साल बाद भी वंदे मातरम् हमारे भीतर जीवित है, हमारे राष्ट्र के भीतर धड़क रहा है और आगे वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन कर रहा है। वंदे मातरम् हमें जोड़ सकता है लेकिन शर्त यही है कि हम इसे विभाजन नहीं, एकता की दृष्टि से देखें। यही इस गीत की सबसे बड़ी गरिमा है और यही इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता भी है।

वंदे मातरम् गाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, राष्ट्रीय एकता का अर्थ सभी समुदायों की भावनाओं का सम्मान करना है, किसी गीत को पहचान की परीक्षा नहीं बनाया जाना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी (AIMIM)

प्रदूषण का आयुर्वेदिक समाधान

प्रकृति की ओर लौटने का समय

भारत में वायु प्रदूषण सिर्फ मौसम का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि अब यह हर उम्र, हर वर्ग और हर धुआँ, वाहन, धूलकण, उद्योग और जलती पराली—इन सभी ने हवा को इतना जहरीला कर दिया है कि साफ़ आसमान अब तस्वीरों में ही दिखने लगा है। ऐसे समय में लोग दवाओं और मास्क पर निर्भर हो गए हैं; लेकिन भारत की पारंपरिक चिकित्सा—आयुर्वेद—हमें ऐसे कई तरीके देती हैं जो प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभावों को कम कर सकते हैं और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं।

आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है—रोग से लड़ाई नहीं, रोग से पहले शरीर को तैयार करना।

प्रदूषण के संदर्भ में यह सिद्धांत सबसे सटीक बैठता है।

इस लेख में हम जानेंगे कि प्रदूषण के बढ़ते खतरे से बचने के लिए आयुर्वेद क्या रास्ते बताता है और कैसे सामान्य दिनचर्या बदलकर हम अपने फेफड़ों, नाक, त्वचा और सांस की रक्षा कर सकते हैं।

1. प्रदूषण शरीर पर क्या असर डालता है? आयुर्वेद की दृष्टि

आयुर्वेद के अनुसार, प्रदूषण हवा के “दोष” को बिगड़ा देता है।

विशेष रूप से वात दोष और पित्त दोष असंतुलित हो जाते हैं।

इसके परिणामस्वरूप—

गले में खराश

बंद या बहनी नाक

सांस लेने में कठिनाई

खांसी और कफ

आंखों में जलन

थकान और सिरदर्द

त्वचा का रुखापन

एलर्जी

ये सभी लक्षण शरीर के भीतर विषाक्तता (टॉक्सिन)

बढ़ने का संकेत हैं।

आयुर्वेद इसे “आम” कहता है—यानी शरीर में जमा वह कचरा, जिसे शरीर बाहर नहीं निकाल पा रहा।

2. नस्य कर्म: प्रदूषण से बचने का पहला

आयुर्वेदिक कथच

आयुर्वेद में नस्य एक अत्यंत महत्वपूर्ण शोधन चिकित्सा है।

इसमें नाक में विशेष औषधीय तेल डाले जाते हैं।

सबसे उपयोगी नस्य तेल—

अनु तेल

तिल का तेल हल्का गर्म करके

घृत (गाय का घी)

कैसे करें?

सुबह खाली पेट या स्नान के बाद

प्रत्येक नथुने में 2-2 बूंद तेल डालें।

लाभ—



नाक की अंदरूनी परत पर एक सुरक्षा कवच बनता है धूल और सूक्ष्म कण फेफड़ों तक नहीं जाते सांस नली प्रदूषण से बचती है

नाक में सूखापन नहीं होता

सिरदर्द कम होता है

बहुत से आयुर्वेदाचार्य कहते हैं कि नस्य न सिर्फ प्रदूषण बल्कि दमा, एलर्जी और साइनस में भी चमत्कारी लाभ देता है।

3. भाप (स्टीम) और धूपन: घर को प्रदूषण-रोधी बनाना

जब प्रदूषण बढ़ता है, हवा में हानिकारक कण लंबे समय तक नासिका में टिक जाते हैं।

आयुर्वेद के अनुसार, स्टीम (स्वेदन) उनके प्रभाव को कम करता है।

कैसे करें?

गर्म पानी की भाप लें

उसमें तुलसी या अजवाइन डालें

5-7 मिनट रोज़ पर्याप्त है

फायदे—

नाक खुलती है

जमा धूल बाहर निकलती है

गले की जलन कम होती है

फेफड़े साफ़ होते हैं

धूपन (Herbal fumigation):

घर में शुद्ध हवा बनाए रखने के लिए आयुर्वेद धूपन का सुझाव देता है।

तुलसी, कपूर, अजवाइन और नीम की सूखी पत्तियों को गर्म तवे पर डालें।

इनकी सुगंध वातावरण को शुद्ध करती है और बैक्टीरिया को नष्ट करती है।

4. प्रदूषण से बचने के लिए आयुर्वेदिक पीने वाली चीजें

आयुर्वेद में कई ऐसे काढ़े और पेय बताए गए हैं जो फेफड़ों को मजबूत करते हैं।

(1) हल्दी वाला दूध

रात को हल्का गर्म दूध में एक चुटकी हल्दी

प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है

(2) अदरक-तुलसी-काली मिर्च की चाय

यह प्रदूषण के कारण होने वाली खांसी और एलर्जी के लिए सबसे कारगर मिश्रण है।

(3) मुलेठी का पानी

गला नरम करता है

फेफड़ों की सूजन कम करता है

(4) गिलाय और आंवला रस

शरीर में प्रतिरोधकता बढ़ाकर प्रदूषण से होने वाली बीमारियों को रोकते हैं।

5. आहार—जो फेफड़ों को ढाल बना देता है

आयुर्वेद कहता है कि “गलत भोजन ही रोगों का आधार है।”

प्रदूषण के समय भोजन को विशेष रूप से हल्का और पचने योग्य रखना चाहिए।

क्या खाना चाहिए?

घी (फेफड़ों को स्वस्थ रखता है)

आंवला

गाजर

नींबू

हरी पत्तेदार सब्जियाँ

गर्म भोजन और सूप

क्या नहीं खाना चाहिए?

तला हुआ खाना

कोल्ड ड्रिंक्स

बासी भोजन

बहुत ठंडा पानी

ये चीजें कफ बढ़ाती हैं और प्रदूषण के दुष्प्रभाव को बढ़ा देती हैं।

6. योग और प्राणायाम—फेफड़ों की वास्तविक सफाई

प्रदूषण से निपटने का सबसे आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक तरीका है प्राणायाम।

कौन से प्राणायाम करें?

अनुलोम-विलोम

भस्त्रिका

कपालभूति (हल्के वेग में)

ब्रह्मरी

ये फेफड़ों में ऑक्सीजन बढ़ाते हैं और शरीर में जमा विषाक्तता कम करते हैं।

कौन से आसन उपयोगी हैं?

भुजंगासन

उष्ट्रासन

धनुरासन

ताडासन

इनसे चेस्ट कैविटी खुलती है और फेफड़े अधिक ताकतवर बनते हैं।

7. आंखों और त्वचा के लिए आयुर्वेदिक सुरक्षा

प्रदूषण का असर सिर्फ़ फेफड़ों पर नहीं, त्वचा और आंखों पर भी होता है।

त्वचा के लिए—

नारियल तेल या घी की हल्की मालिश

एलोवरा जेल

नीम के पानी से हल्का चेहरा धोना

आंखों के लिए—

गुलाब जल

त्रिफला जल (आयुर्वेद में सबसे श्रेष्ठ नेत्र-शोधन)

8. आयुर्वेदिक जीवनशैली: छोटी आदतें, बड़े फायदे

1. सुबह घर के पौधों को पानी दें

हवा की नमी बढ़ती है और धूल कम उड़ती है।

2. नाक पर घी लगाने की आदत डालें

नथुने प्रदूषण के कणों से सुरक्षित रहते हैं।

3. खिड़की-दरवाजे सुबह जल्दी खोलें

ताजी हवा अंदर आए, रात की दूषित हवा बाहर जाए।

4. शरीर को गर्म रखें

ठंडे के मौसम में प्रदूषण का प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है।

ये आदतें छोटी लगती हैं, पर इनके परिणाम लंबे समय तक शरीर को सुरक्षित रखते हैं।

आयुर्वेद कहता है—प्रदूषण रोका नहीं जा सकता, लेकिन शरीर को मजबूत बनाया जा सकता है।

आज का प्रदूषण हमारी जीवनशैली की देन है। इसे तुरंत समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन आयुर्वेद हमें सिखाता है कि शरीर को इतना मजबूत बनाया जाए कि वह

संत वामाक्षेपा जी: तारा माता की अनंत कृपा के सागर में लीन भक्त

स्व

र्णि बंगभूमि हमेशा से शक्ति-उपासना और

तांत्रिक साधना की प्रधान पीठिका रही है। इस परम पवित्र भूमि में भक्ति और शक्ति के प्रेममय माधुर्य तथा दिव्य ज्ञानमय ऐश्वर्य की अभिव्यक्ति समय-समय पर अमिट समीचीन ढंग से होती रही है। संत रामप्रसाद की काली उपासना और रामकृष्ण परमहंस की शक्ति साधना से चिरसौरवान्वित इस तपोमयी भूमि में प्रसिद्ध अधोरी संत वामाक्षेपा ने तारा देवी-महाकाली श्यामा की उपासना कर शाक्त जगत में जो नाम कमाया, उसका मूल्यांकन लेखनी के वश की बात नहीं। वामाक्षेपा सिद्ध महात्मा थे। जगत के कण-कण में, जड़ और चेतन में उन्होंने अपनी आराध्य जगज्जननी तारा की ही अभिव्यक्ति देखी। वे आजीवन देवी के ही अनंत ऐश्वर्य, सौंदर्य और माधुर्य के सागर में निमग्न रहे। संत वामाक्षेपा रामकृष्ण परमहंस के समकालीन थे। जिस समय दक्षिणेश्वर मंदिर में रामकृष्ण काली के पदपद्म की आराधना में तल्लीन थे, उस समय वे बंग भूमि में द्वारिका नदी के तट पर तारापीठ में भगवती तारा का मनोरंजन कर रहे थे।

तारापुर बंगाल की वीर भूमि जनपद का एक प्रसिद्ध स्थान है। यह द्वारिका नदी के तीर पर अवस्थित है। यहाँ तारा देवी के मंदिर में बड़े-बड़े शाक्त संतों ने सिद्धि प्राप्त की थी। इसी वीरभूमि जनपद ने गीत गोविंद के रचयिता परमकृष्ण-भक्त महाकवि जयदेव और नित्यानन्द अवधूत को जन्म दिया था। तारापीठ में ही वशिष्ठ ने प्राचीन काल में तारा देवी की आराधना कर चिद्धि प्राप्त की थी। तारापीठ में ही सती के नयन का तारा गिरा था, इसीलिए यह स्थान शाक्तों के लिए सिद्धि पीठ बन गया। मध्यकाल के अंतिम चरण में तारापुर मुस्लिम शासक के अधीन था। नाटोर राज्याधीश्वरी रानी भवानी ने तारापुर किसी दूसरे भूमिभाग के बदले में ले लिया था। नाटोर राज्य के शाक्त शासक राजा रामकृष्ण तारा देवी के बड़े भक्त थे। उन्होंने राज्य की ओर से तारा देवी के भोग आदि की व्यवस्था कर दी थी। वामाक्षेपा के गुरु मोक्षदानन्द और उनके गुरु आनंदनाथ तारापीठ के कौलिक पद को सुशोभित कर चुके थे। अधोरी संत वामाक्षेपा तारा देवी के ही उपासक थे। अधोरी संतों में उन्हें गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। वामाक्षेपा देखने में वाह्याकृति से बड़े भयकर और भीषण लगते थे, पर उनसे साहस पूर्वक मिलने के बाद उनके उदार और कोमल हृदय तथा शिष्टता और शील का पता लगता था। वे अपने आप को लोक संसार से दूर रखने के लिए पागल की तरह आचरण करते थे। तारापुर के शमशान में निरंतर निवास कर उन्होंने तारा देवी की चरणभक्ति से जीवन में शिव का साक्षात्कार किया। इस पवित्र सिद्धि पीठ की मट्टी में तारा माता की कृपा का प्रत्येक कण भक्तों के हृदय को स्पर्श करता है, और वामाक्षेपा जैसे महापुरुषों की साधना ने इसे और भी दिव्य बना दिया। यहाँ की वायु में शक्ति की गूंज है, जो हर आने वाले को अपनी गोद में समेट लेती है।

जन्म और बाललीला: भक्ति का प्रारंभिक उद्य

वामाक्षेपा ने तारापुर से थोड़ी दूर पर आटलाग्राम में संवत् 1891 विक्रम में एक धार्मिक ब्राह्मण परिवार

तारापीठ: शक्ति उपासना की स्वर्णम् भूमि



मैं जन्म लिया था। उनके पिता सर्वानन्द चट्टोपाध्याय बड़े सदाचारी और भगवद्भक्त थे। उनकी पत्नी भी बड़ी सुशील और सती साध्वी थी। वामाक्षेपा के बचपन का नाम वामाचरण था और उनके छोटे भाई का नाम रामचंद्र था। उनकी दो बहनें थीं। बाल्यावस्था में वामाचरण काली की मूर्ति बनाकर खेल-ही-खेल में पूजा किया करते थे। भगवान के चरित्र-विशेष रूप से रामलीला में उनकी बड़ी रुचि थी। शैशवावस्था में ही पिता का परलोकवास हो जाने से उनकी शिक्षा-दीक्षा का उचित प्रावधान न हो सका। यौवन के प्रथम कक्ष में प्रवेश करते ही परिवार के भरण-पोषण का भार वामाचरण के कंधों पर आ पड़ा। विवाह का समय उपस्थित देखकर माता ने उन्हें काम-काज करने की प्रेरणा दी। वामाचरण निष्ठुर हो गए। वे तारा देवी के मंदिर में गए। उन्होंने तारा माता से निवेदन किया। जगज्जननी की कृपा से उन्हें काम-काज करने की प्रेरणा प्राप्त हुई। वामा ने घर जाकर अपनी मां से कहा कि मैं काम करूँगा। बाहर जाकर रुपया कमाऊंगा। माता ने ममता भरी दृष्टि से वामा को देखा, कहा, 'तू मेरा पागल लटका है, मैं तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक चाहती हूँ, तुम घर पर रहकर खेती करो।' वामा ने कहा 'मा, मैं ब्राह्मणकुमार हूँ, यद्यपि मेरी शिक्षा-दीक्षा नहीं के बराबर है, तो भी मैं ठाकुरमंदिर में जाकर पुजारी को काम तो कर ही सकता हूँ।' मां ने स्वीकृति दे दी। कुछ दिनों तक वे एक मंदिर में ठाकुर की पूजा करते रहे, पर बाद में उन्होंने मालिक से ठीक-ठीक बात बता दी कि मैं अयोग्य हूँ, मुझसे भगवान की पूजा नहीं हो सकती। वामा ने पुजारी का काम छोड़ दिया। इस समय उनकी अवस्था लगभग बारह साल की थी। वे अपनी बहन के घर आकर रहने लगे, पर उनका मन स्थिर न रह सका। उनके हृदय में वैराग्य और साधना की तररों उठ रही थीं। उन्होंने अल्पावस्था में घर का त्याग कर दिया, तारापीठ में चले आए। उस समय प्रथान कौलिक मोक्षदानन्द थे। उनके संपर्क में रहकर वामा

पड़ी। वामा ने अपने स्वजनों को देखा कि वे शब दाह के लिए नदी-तट पर उपस्थित हैं। वे तारा पीठ की ओर शमशान में शब का दाह संस्कार न कर नदी की उसी ओर अंत्येष्टि संपन्न करना चाहते थे। बाढ़ के कारण शमशान भूमि में शब ले आना कठिन था। वामा समझ गए कि मेरी मां ने महाप्रस्थान किया है। महायोगी वामाक्षेपा, जिन्हे गांव वाले नितांत क्षेप-पागल कहकर पुकारते थे, बाढ़ के वेग का सामना कर दूसरी ओर पहुंच गए। मातृ-वियोग ने वामाक्षेपा जैसे महायोगी को भी विचलित कर दिया। उनके नयनों से अश्रुपात होने लगा। उन्होंने तारा देवी को संबोधन कर कहा, जगज्जननी क्या आप के मंदिर के निकट शमशान में मेरी मां शरण न पाएंगी? अवश्य पाएंगी। वे लाश को लेकर नदी में कूद पड़े और बाट-की बात में तारापीठ के निकट शमशान में पहुंचकर उन्होंने बड़े समारोह से मातृशब्द का दाह-संस्कार किया। ब्रह्मभोज-श्राद्ध दिवस के दो दिन पहले ही घर जाकर उन्होंने अपने छोटे भाई रामचंद्र से कहा, 'आगे का मैदान साफ कर लो। सात-आठ गांव के ब्राह्मणों को श्राद्ध-भोज के लिए निर्मिति कर दो।' रामचंद्र ने पागल भाई की बात पर ध्यान नहीं दिया। श्राद्ध के दिन दूर-दूर से खाद्य पदार्थ—दही-चूड़ा आदि के भार आते देखकर रामचंद्र तथा गांव के अन्य लोग आश्चर्यचकित हो गए। बहुत से निर्मित ब्राह्मण उपस्थित हो गए। तारा पीठ से स्वयं वामाक्षेपा भी आ चुके थे। थोड़ी देर में आकाश काले-काले मेघों से आच्छन्न हो उठा। वृष्टि होने ही वाली थी। सब लोग चिंतित हो उठे।

'दादा, जिस प्रकार आप ने समस्त प्रबंध किया उसी प्रकार वृष्टि भी रोक दीजिए।' रामचंद्र ने वामा के चरण का स्पर्श किया। वामा ने जगज्जननी तारा का ध्यान किया कि मां यदि ब्राह्मण बिना भोजन किए ही चले जाएंगे तो मेरी जननी का श्राद्ध अधूरा रह जाएगा। तारा ने वामाक्षेपा की मनोकामना पूरी की। उनकी कृपा से आकाश निर्मल हो गया। वृष्टि की संभावना का अंत हो गया। विधिपूर्वक श्राद्ध और ब्राह्मण-भोजन संपन्न होने पर वामाक्षेपा तारापीठ चले आए। उनकी सिद्धि ने उपस्थित जनता का मन मुग्ध कर लिया। वह वामा के चरणों में नत हो गई। उनका समस्त जीवन तारा के चरणों में अर्पित था। उन्होंने अपने आप को मां की गोद में सुक्षित कर निर्भयता प्राप्त कर ली थी। वे बालक की भाँति वात्सल्य ज्ञान से निःस्वार्थ शून्य होकर मां की प्रेममयी-वात्सल्य मयी गोद में खेला करते थे। मां भोजन दिलाती तो खा लेते थे। कपड़ा पहनाती तो पहन लेते थे। बालक की तरह दो-एक बार तारा के सामने उन्होंने मूत्र त्याग भी कर दिया। उनकी दृष्टि में यह आचरण सर्वथा दोषरहित था। बालक तो ऐसा किया ही करता है।

नाटोर राज्य के तारापीठस्थ राजकर्मचारियों ने मंदिर के भोग आदि की व्यवस्था अपने हाथ में ले ली। माता के मंदिर को अपवित्र करते रहने का उन पर दोष लगाया। वामा का प्रसाद पाना बंद हो गया। वे कई दिन तक निराहर रहे, पर एक क्षण के लिए भी उन्होंने मां का नाम विष्वासूत्र में तृप्त हो जाया करते थे। उनके मुख में निरंतर 'तारा-तारा' का उच्चारण होता रहता था।

माता का महाप्रस्थान: चमत्कारपूर्ण कृपा का दर्शन

एक दिन वे द्वारिका नदी में स्नान कर रहे थे। नदी बाढ़ पर थी। चारों ओर पानी ही-पानी का राज्य था। नदी की दूसरी ओर उन्हें दूर से ही 'हरिनाम' की ध्वनि सुनाई

बंगाल में बाबरी का साया हुमायूं की ईंटें और सियासत का तूफान

पर्विचम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। यहां के विधायक हुमायूं कबीर ने अचानक घोषणा की कि वे बाबरी मस्जिद जैसी एक नई मस्जिद बनवाएंगे। यह बात 6 दिसंबर 2025 को और तेज हो गई, जब कबीर ने वाकई में इसकी आधारशिला रख दी। बाबरी मस्जिद का नाम आते ही पुरानी यादें ताजा हो गईं। 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी, और अब बंगाल में इसका नाम लेते ही सियासत गर्म हो गई। कबीर का कहना है कि यह मस्जिद शांति का प्रतीक बनेगी, लेकिन कई लोग इसे उक्सावा मान रहे हैं। मुर्शिदाबाद एक ऐसा इलाका है जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय रहते हैं। यहां की आबादी में मुस्लिम बहुमत है, लेकिन छोटी-छोटी बातों पर तनाव होता रहता है। कबीर ने कहा कि वे राम मंदिर के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि सिर्फ अपनी धार्मिक भावनाओं को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन TMC पार्टी ने इसे गलत बताया। पार्टी के नेता फिरहाद हकीम ने कहा कि कबीर द्वृष्ट बोल रहे हैं और वे BJP के एंजेंट हैं। यह विवाद सिर्फ मस्जिद का नहीं, बल्कि बंगाल की सियासत का भी है। ममता बनर्जी की सरकार पहले से ही विपक्ष के निशाने पर है। BJP इसे वोट बैंक की राजनीति बता रही है, जबकि TMC कह रही है कि कबीर ने पार्टी को बदनाम किया। स्थानीय लोग दो हिस्सों में बंट गए हैं। कुछ कबीर के समर्थन में सड़कों पर उत्तर आए, तो कुछ चुपचाप डर महसूस कर रहे हैं। यह घटना बंगाल के आगामी चुनावों पर असर डाल सकती है। क्या यह शांति का संदेश देगी या नया दंगा भड़काएगी? सवाल यही है जो हर कोई पूछ रहा है। कुल मिलाकर, यह विवाद दिखाता है कि धार्मिक मुद्दे कितनी आसानी से राजनीति में घुस जाते हैं।

हुमायूं कबीर का साहस: 6 दिसंबर को ईंटें सिर पर, नींव रखी

6 दिसंबर 2025 का दिन मुर्शिदाबाद के लिए यादगार बन गया। निलंबित TMC विधायक हुमायूं कबीर ने भारी सुरक्षा के बीच बेलडांगा में बाबरी मस्जिद जैसी नई मस्जिद की नींव रख दी। सुबह से ही हजारों लोग जमा हो गए। कई समर्थकों ने सिर पर ईंटें रखकर मार्च निकाला, जैसे बाबरी की याद दिलाने के लिए। कबीर ने मंच पर कहा, “जमीन नहीं तो मस्जिद कहां बनेगी? आज दिखा दूंगा सबको।” उन्होंने दावा किया कि जिला प्रशासन ने उन्हें पूरा सहयोग दिया है। पुलिस ने 2000 से ज्यादा जवान तैनात किए थे, ताकि कोई हादसा न हो। कार्यक्रम में सज्जी अरब के मौलवी भी आए, और 40,000 बिरयानी के पैकेट बांटे गए। कबीर ने कहा कि यह मस्जिद 5 एकड़ जमीन पर बनेगी, और इसका खर्च वे खुद उठाएंगे। लेकिन सवाल उठा कि जमीन कहां से आई? कबीर ने पहले कहा था कि अगर जमीन नहीं मिली तो वे सड़क पर ही बनवाएंगे। अब वे कह रहे हैं कि सब कानूनी है। स्थानीय लोग उत्साहित दिखे, लेकिन कुछ ने डर जताया कि इससे दंगे हो सकते हैं। कबीर की यह हरकत

विवाद की जड़: बाबरी मस्जिद का नाम क्यों आया बीच में?



उनकी पुरानी आदत है। वे पहले भी कई बार विवादों में फंसे हैं। 10 साल पहले भी TMC ने उन्हें निकाला था। लेकिन कबीर हार मानने वाले नहीं। उन्होंने कहा, “मैं राम मंदिर का सम्मान करता हूं, लेकिन हमारी भावनाओं की भी कदर होनी चाहिए।” यह शिलान्यास सिर्फ एक इमारत का नहीं, बल्कि कबीर के राजनीतिक सफर का नया अध्याय है। वे कहते हैं कि TMC ने उन्हें संस्पेंड किया, लेकिन जनता उनके साथ है। क्या यह कदम उन्हें नया समर्थन देगा? या फिर और मुश्किलें बढ़ाएगा? बंगाल की सड़कों पर यह बहस जारी है।

TMC का गुरुसा: निलंबन से आगे, एंजेंट का ठप्पा

TMC पार्टी हुमायूं कबीर के इस कदम से बेहद नाराज है। 4 दिसंबर को ही पार्टी ने उन्हें तत्काल संस्पेंड कर दिया। कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने कहा, “हुमायूं झूठा है, वह BJP का एंजेंट है।” उनका मतलब था कि कबीर जानबूझकर विवाद खड़ा कर TMC को बदनाम कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने चुप्पी साथी, लेकिन पार्टी के अन्य नेता सक्रिय हो गए। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद का नाम लेना उचित नहीं, खासकर जब अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है। TMC का कहना है कि कबीर ने पार्टी लाइन से हटकर बयान दिए। पहले कबीर ने कहा था कि वे 22 दिसंबर को नई पार्टी बनाएंगे, और 135 सीटों पर लड़ेंगे। यह सुनकर TMC और चिढ़ गई। पार्टी के एक नेता ने कहा, “हमने उन्हें कई मौके दिए, लेकिन वे सुधरे नहीं।” संस्पेशन के बाद भी कबीर ने कहा कि वे पार्टी छोड़ने वाले नहीं, लेकिन अब लगता है कि रास्ते अलग हो गए। TMC

की चिंता यह है कि यह विवाद मुस्लिम वोट बैंक को प्रभावित करेगा। बंगाल में 30% मुस्लिम आबादी है, और ममता इसी पर निर्भर हैं। विपक्ष BJP ने TMC पर हमला बोला, कहा कि वे धार्मिक उन्माद फैला रही हैं। लेकिन TMC ने पलटवार किया कि BJP ही असली उक्साने वाली है। हकीम ने कहा, “कबीर ने कहा था कि मस्जिद गिराने की हिम्मत हो तो गिरा दो, यह BJP की भाषा है।” यह निलंबन सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पार्टी की एक जुट्टा का संदेश है। क्या कबीर वापस लौटेंगे? या नई पार्टी से चुनौती देंगे? TMC के लिए यह परीक्षा का समय है।

सियासत के रंग: BJP की आलोचना और सड़कों पर तनाव

यह विवाद बंगाल की सियासत को कई रंग दे रहा है। BJP ने कबीर के शिलान्यास को भड़काऊ बताया। पार्टी के नेता दिलीप घोष ने कहा, “यह TMC की साजिश है, मुस्लिम वोट के लिए।” उन्होंने ममता सरकार पर कानून-व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाया। मुर्शिदाबाद में तनाव बढ़ गया, सड़कों पर भारी पुलिस तैनाती रही। स्थानीय हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन हिंसा नहीं हुई। कबीर के समर्थकों ने कहा कि यह उनका हक है, जबकि विपक्ष ने इसे संविधान के खिलाफ बताया। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने चेतावनी दी कि कानून तोड़ने वालों से सख्ती होगी। उन्होंने कहा, “बंगाल में ऐसी हरकतों की इजाजत नहीं।” यह बयान TMC के लिए झटका था। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। X पर लोग कबीर को हीरो बता रहे हैं, तो कुछ उन्हें पागल। एक पोस्ट में

लिखा, “6 दिसंबर को बाबरी की याद दिला दी।” लेकिन ज्यादातर लोग शांति की अपील कर रहे हैं। बंगाल पुलिस ने कहा कि वे निगरानी रखेंगे। यह विवाद दिखाता है कि धार्मिक मुद्दे कैसे राजनीतिक हथियार बन जाते हैं। BJP इसे 2026 चुनाव में इस्तेमाल कर सकती है, जबकि TMC को सफाई देनी पड़ेंगी। स्थानीय व्यापार प्रभावित हुआ, बाजार बंद रहे। लोग डर रहे हैं कि छोटी चिंगारी बड़ा आग न लगाए। कुल मिलाकर, यह घटना बंगाल के सामाजिक ताने-बाने को परख रही है। क्या नेता समझेंगे कि शांति ही सबसे बड़ा धर्म है?

आगे की राह: नई पार्टी का एलान और सबक

हुमायूं कबीर का यह कदम उनके राजनीतिक सफर में नया मोड़ ला सकता है। उन्होंने कहा कि 22 दिसंबर को वे नई पार्टी बनाएंगे, जो BJP और TMC दोनों से लड़ेंगी। कबीर का दावा है कि उनके पास हजारों समर्थक हैं। लेकिन चुनौतियां बड़ी हैं। बिना पार्टी के वे अकेले कैसे लड़ेंगे? TMC कह रही है कि कबीर का भविष्य काला है। यह विवाद बंगाल को एक सबक दे रहा है। धार्मिक भावनाओं से खेलना खतरनाक है। अयोध्या का मामला अदालत ने सुलझाया, लेकिन यहां तो सिर्फ बयानबाजी है। स्थानीय लोग चाहते हैं कि शांति बनी रहे। मस्जिद बनेगी या नहीं, यह समय बताएगा, लेकिन सियासत जरूर गर्म रहेगी। कबीर की कहानी दिखाती है कि एक व्यक्ति कैसे पूरे राज्य को हिला सकता है। क्या ममता सरकार इससे सीख लेगी? या फिर ऐसे विवाद और बढ़ेंगे? बंगाल के लोग बस यहीं सोच रहे हैं कि उनका भविष्य सुरक्षित रहे। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि राजनीति धर्म से ऊपर होनी चाहिए।

भारत-पाक सीमा फिरोजपुर पर जगद्गुरु महाब्रह्मऋषि श्री कुमार स्वामी जी का आगमन, गुरु माँ भी रहीं साथ



भारतश्री व्यूरो

भा

रत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था और सम्मान प्रोटोकॉल के विच जगद्गुरु महाब्रह्मऋषि श्री कुमार स्वामी जी ने अधिकारियों के कार्य और अनुशासन की सर्वोच्चता की।

यात्रा के दौरान स्थानीय श्रद्धालु और विभिन्न राज्यों से आए अनुयायी भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कई लोगों ने इसे सीमा पर आधारित और राष्ट्रीय भावों का अद्भुत संगम बताया। संशेल पीड़िया पर भी उनके आगमन के दृश्य तेजी से बायरल हुए, जिनमें भावुक प्रतिक्रियाएँ और शुभकामनाएँ देखी गईं।

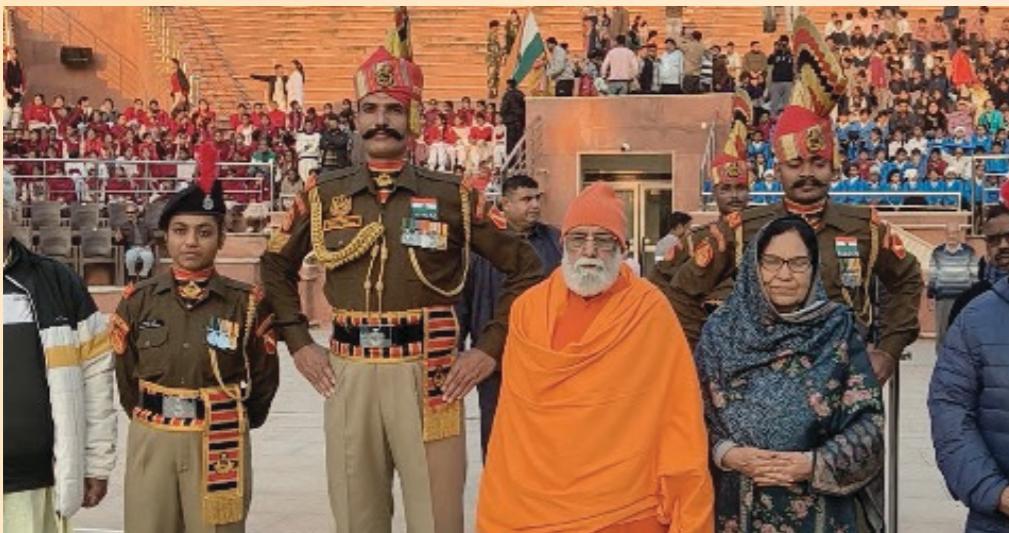
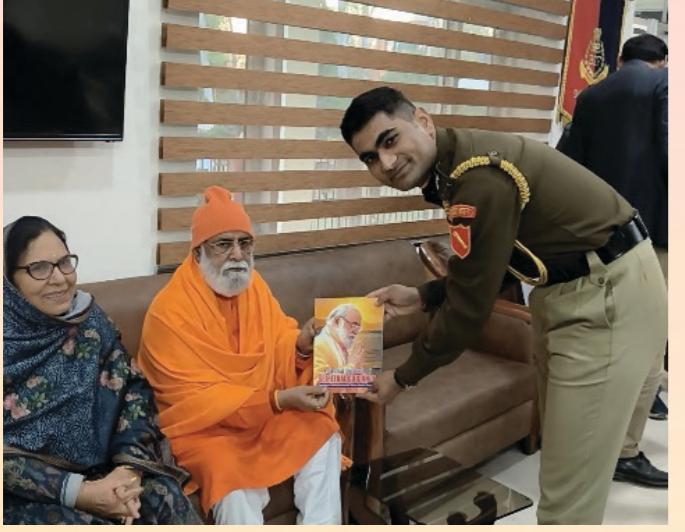
सीमा चौकी पर पहुंचकर जगद्गुरु जी ने जवानों से संवाद किया और उनकी लगन व राष्ट्रसेवा की भावना की सराहना की। उन्होंने कहा कि सीमा पर डटे जवान देश की शांति, अखंडता और सुरक्षा के सबसे बड़े संरक्षक हैं। गुरु माँ भी सीमा की मिट्टी को नमन किया और राष्ट्र के लिए मंगलकामना की।

इस मौके पर बीएसएफ अधिकारियों ने उन्हें सीमा सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ दीं। उन्होंने आधुनिक निगरानी प्रणाली, गश्त व्यवस्था और सुरक्षा प्रोटोकॉल के विवरण साझा किया। जगद्गुरु जी ने अधिकारियों के कार्य और अनुशासन की सर्वोच्चता की।

यात्रा के दौरान स्थानीय श्रद्धालु और विभिन्न राज्यों से आए अनुयायी भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कई लोगों ने इसे सीमा पर आधारित और राष्ट्रीय भावों का अद्भुत संगम बताया। संशेल पीड़िया पर भी उनके आगमन के दृश्य तेजी से बायरल हुए, जिनमें भावुक प्रतिक्रियाएँ और शुभकामनाएँ देखी गईं।

सीमा चौकी पर पहुंचकर जगद्गुरु जी ने जवानों से संवाद किया और उनकी लगन व राष्ट्रसेवा की भावना की सराहना की। उन्होंने कहा कि सीमा पर डटे जवान देश की शांति, अखंडता और सुरक्षा के सबसे बड़े संरक्षक हैं। गुरु माँ भी सीमा की मिट्टी को नमन किया और राष्ट्र के लिए मंगलकामना की।

इस मौके पर बीएसएफ अधिकारियों ने उन्हें सीमा सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ दीं। उन्होंने आधुनिक निगरानी प्रणाली, गश्त व्यवस्था और सुरक्षा प्रोटोकॉल के विवरण साझा किया। जगद्गुरु जी ने अधिकारियों के कार्य और अनुशासन की सर्वोच्चता की।



मां दुर्गा के अनूठे अनुभव

बीपी और शराब की लत हुई खत्म

परम पूज्य सदगुरुदेव जी, मुझे कई सालों से अपने दोस्तों की दुरी संगत के कारण शराब की लत लग गई थी। इसकी वजह से भयंकर बीमारी की बीमारी भी लग गई। डाक्टरों से दवाई भी ली परंतु शराब की लत नहीं हटी। अंत में मैंने समागम में सर्वरोग निवारक औषधि ग्रहण की और इसे अधिनियंत्रित जल में प्रयोग करके स्नान किया। मात्र 15 दिन में मुझे शराब से नफरत होने लगी और परम पूज्य सदगुरुदेव जी की कृपा से शराब पूरी तरह हट गई और मेरा बीपी भी नारंग हो गया।

मनोज वधवा, पटियाला, पंजाब

सरवाइकल से मिली मुक्ति

परम पूज्य सदगुरुदेव जी, मैं पिछले दस सालों से डैंड्रफ के भयंकर रोग से बहुत परेशान रहता था। मेरे सिर में सफेद चक्रते हो गए थे। बालों से सफेद सीकरी झड़ती रहती थी। सिर में खुजली बहुत चलती थी, कई तरह से शैम्पू इस्तेमाल किए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। मैंने समागम में सर्वरोग निवारक औषधि ग्रहण की और विधिपूर्वक इसका प्रयोग किया। मैं आज बहुत खुश हूं क्योंकि मैं इस रोग से मुक्त हो चुका हूं।

निशा छाबड़ा, अंबाला, हरियाणा

ब्लांड सर्कुलेशन हुआ ठीक

परम पूज्य सदगुरुदेव जी, मैं पिछले पांच सालों से नर्वस सिस्टम की प्राकृतम से जड़ रही थी। मेरी नर्सों में ब्लांड सर्कुलेशन ठीक नहीं था। इसके कारण मुझे चक्रवर आते थे और हाथ-पैर फुकते थे। न मैं ठीक से जांब कर पाती थी और न ही रात को सो पाती थी। डाक्टरों के पास गए तो उन्होंने दवाएं दी जिससे मुझे आलस बना रहता था। मैंने समागम में जाकर सर्वरोग निवारक औषधि ग्रहण की और विधिपूर्वक उसका सेवन किया। इसका परिणाम यह हुआ कि इस असाध्य रिस्ति से मुक्त हो गई और अब मैं पूरी तरह से ठीक हूं।

किरण सिंह, कानपुर, उत्तर प्रदेश

जोड़ों के दर्द से बहुत परेशान थी। मैं रात को बेड पर चैन से नहीं सो पाती थी। मैंने थैरेपी करवाई लेकिन कोई आराम नहीं मिला और दवाई भी खाई। दवाई खाने के साइड इफेक्ट हुए जिससे मैं बहुत परेशान रहती थी। सिर में खुजली बहुत चलती थी, कई तरह से शैम्पू इस्तेमाल किए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। मैंने इसे कर्म व बुटनों पर लाया, स्नान किया और ग्रहण किया। मैंने इसे कर्म व बुटनों पर लाया, स्नान किया और ग्रहण किया। इसके दर्द से मुक्त हो गई हूं।

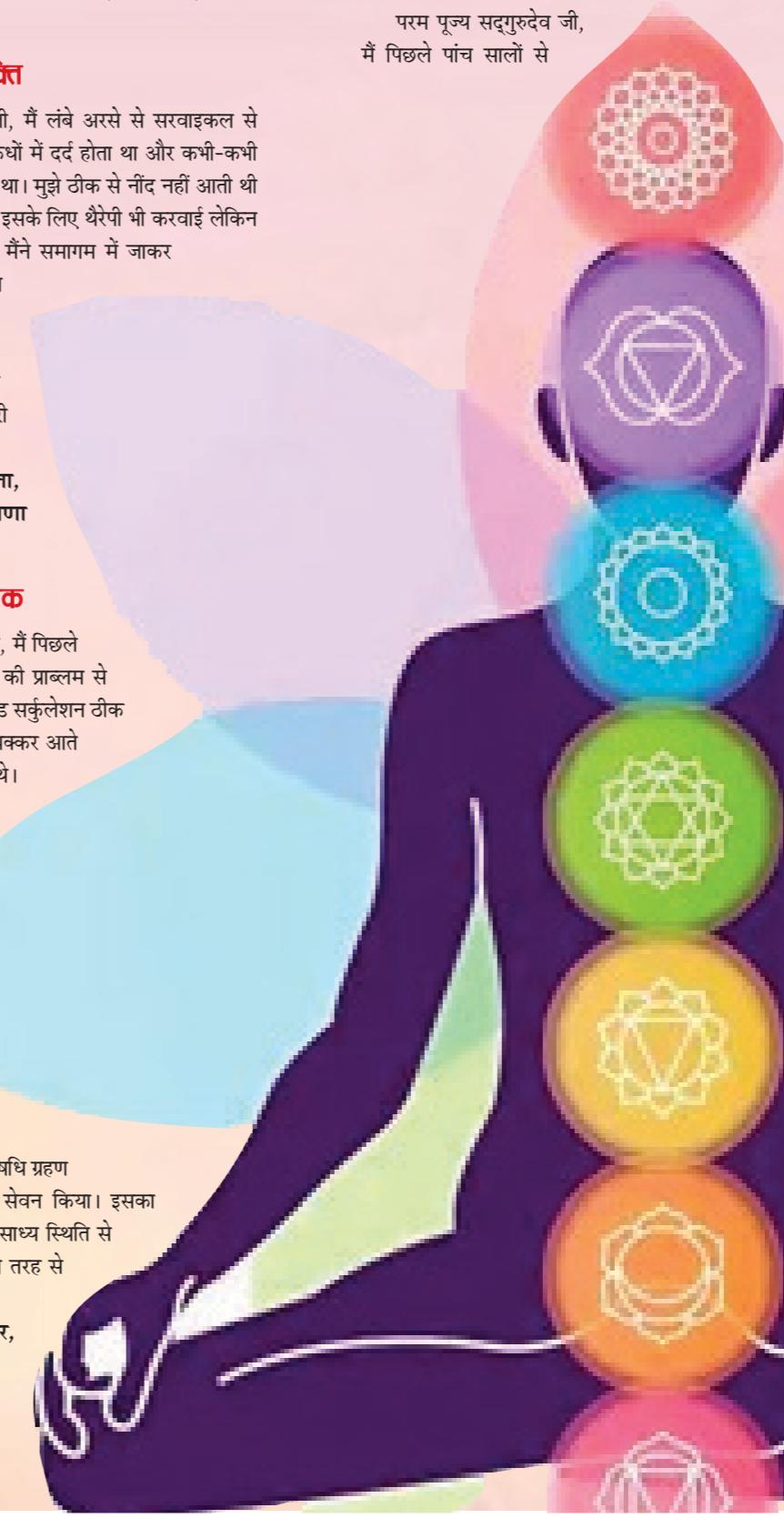
रमा गोस्वामी, सूरत, गुजरात

भयंकर पीलिया से मिली मुक्ति

परम पूज्य सदगुरुदेव जी, मैं पिछले पांच सालों से पीलिया से पीड़ित था। मेरी जिन्दगी एक तरह से नक्क बन गई थी। इसके लिए मैं बराबर दवाई ले रहा था। मुझे हाई ब्लड प्रेशर के साथ शुगर की बीमारी भी हो गई थी। डाक्टर ने कहा कि आपको कोपो थैरेपी भी करवानी पड़ेगी। मैं और मेरा परिवार बहुत परेशान था। मैंने समागम में सर्वरोग निवारक औषधि ग्रहण की इसका प्रयोग मैंने अपने सिर पर किया और इसे पानी के साथ दवा के रूप में खाया था। इसका प्रभाव देखकर मैं

आज भी हैरान हूं कि मुझे न तो पीलिया है, न ही ब्लड प्रेशर और शुगर है।

राम कुमार, चमुना नगर, हरियाणा



लाल हँडा अब फीका क्यों पड़ रहा है?

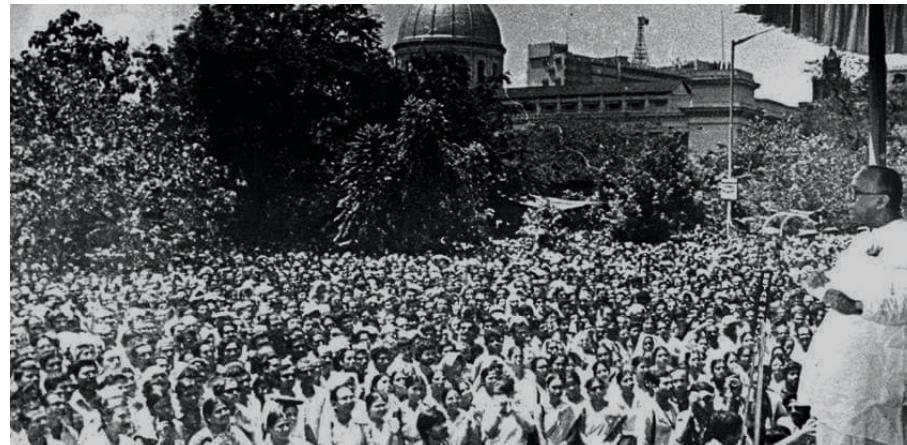
बंगाल से त्रिपुरा तक वाम राजनीति के ढलते सूरज की कहानी

@ अर्पित शुक्ला

भारत की राजनीति में वह दौर आ गया है जब दल आज अपने अस्तित्व तक बचाने के लिए जूँड़ रहे हैं। यह वही वाम मोर्चा है जिसने न सिर्फ मजदूर-किसान आंदोलनों को दिशा दी, बल्कि भारतीय लोकतंत्र को वैचारिक गहराई भी दी। आज उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि कभी जिन राज्यों को लेफ्ट का अभेद्य किला कहा जाता था, वे अब लेफ्ट के लिए राजनीतिक रेगिस्तान में बदलते जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल- जहां वाम दलों ने लगातार 34 साल तक शासन किया—अब ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है कि CPI(M) विधानसभा में एक भी सीट नहीं जीत सकी। त्रिपुरा, जहां माणिक सरकार की छवि ईमानदारी की मिसाल मानी जाती थी और वाम दलों ने 25 साल लगातार सत्ता संभाली, आज वहां भी लेफ्ट तीसरे नंबर पर सिमट चुका है। यह कहानी सिर्फ चुनावी नतीजों के उतार-चढ़ाव की नहीं, बल्कि उस विचारधारा के डगमगाने की है जिसने कभी भारत में वाम राजनीति की लहर पैदा की थी।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में लेफ्ट फ्रंट की पकड़ कभी इतनी मजबूत थी कि राज्य में सत्ता परिवर्तन की कल्पना तक असंभव लगती थी। ज्योति बसु की स्थिर छवि और पार्टी का मजबूत कैडर उन दिनों लेफ्ट की रीढ़ थे। भूमि सुधार और पंचायत व्यवस्था ने ग्रामीण बंगाल में पार्टी को ऐसा आधार दिया जिसे 30 साल से अधिक समय तक कोई नहीं हिला पाया। लेकिन समय बदला और 2007 का नंदीग्राम, फिर सिंगर आंदोलन पार्टी की दिशा बदलने का टर्निंग पॉइंट बन गया। किसानों के बीच वही भरोसा जो वाम दलों का सबसे बड़ा राजनीतिक पूँजी था, धीरे-धीरे खत्म होने लगा। इसका असर सिर्फ ग्रामीण इलाकों में नहीं बल्कि शहरी, शिक्षित और युवा वर्ग पर भी पड़ा, जिसने विकल्पों की ओर देखना शुरू कर दिया। 2016 के चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन करने के बावजूद CPI(M) की सीटें घटकर 26 रह गईं। और 2021 में तो लेफ्ट का बंगाल में सियासी सूर्य ही अस्त हो गया। पार्टी शून्य सीट पर आ गई। यह सिर्फ हार नहीं थी, बल्कि उस विचारधारा की टूटन थी जिसने दशकों तक बंगाल की राजनीति को दिशा दी थी।

इसी तरह त्रिपुरा का राजनीतिक इतिहास भी वामपंथ की लंबी यात्रा का गवाह है। माणिक सरकार के नेतृत्व में राज्य में ऐसी राजनीतिक स्थिरता और पारदर्शिता बनी जिसने लेफ्ट को पूर्वोत्तर का सबसे मजबूत स्तंभ बना दिया। लेकिन 2018 का चुनाव आया और इस स्थिरता की नींव भरभराकर गिर गई। युवा मतदाता नई अर्थिक और सामाजिक आकंक्षाओं के साथ आगे बढ़ चुका था जबकि वाम दल अपने पुराने नारों और पारंपरिक तरीकों पर टिके हुए थे। बीजेपी ने जमीन पर तेजी से काम किया, नए सामाजिक समूहों से संवाद स्थापित किया और वाम दलों का पारंपरिक वॉट बैंक आदिवासी इलाके तक में खिसक गया। लेफ्ट सत्ता से बाहर हुई और सिर्फ 16 सीटों पर सिमट गई। 2023 में वापसी का मौका भी हाथ से



निकल गया और पार्टी तीसरे नंबर पर चली गई। त्रिपुरा में यह हार वाम राजनीति के उस दौर का अंत थी जो 25 साल तक कायम रहा था। अब सवाल यह है कि वाम राजनीति का ग्राम इतनी तेजी से क्यों गिरा? इसका एक बड़ा कारण यह है कि वाम दल भारतीय समाज के बदलते स्वरूप को समझने में पीछे रह गए। आज की राजनीति सिर्फ वर्ग संघर्ष या मजदूर-किसान मुद्दों से संचालित नहीं होती है। आज राजनीति जाति समीकरण, क्षेत्रीय आकंक्षाओं, डिजिटल अर्थव्यवस्था, युवा रोजगार, शहरीकरण और सामाजिक विमर्श के नए मॉडल से प्रभावित होती है। इन सभी मोर्चों पर वाम दलों की उपस्थिति कमज़ोर दिखाई देती है। पुरानी शैली के भाषण, पारंपरिक जनसंपर्क और वैचारिक कठोरता नए दौर के तेज़, तकनीकी और व्यावहारिक राजनीति के सामने कमज़ोर पड़ गई। दूसरी तरफ बीजेपी और क्षेत्रीय दलों ने न सिर्फ संगठनात्मक स्तर पर पैठ बढ़ाई, बल्कि सोशल मीडिया और ग्रामीण-शहरी दोनों

मोर्चों पर ऐसी पकड़ बनाई कि वाम दल इन परिवर्तनों के साथ तालमेल नहीं बिठा सके।

बंगाल और त्रिपुरा की हार के बाद अब लेफ्ट के पास एकमात्र बड़ा गढ़ बचा है—केरल। लेकिन यहां भी स्थिति आसान नहीं है। केरल के 2026 के चुनाव से पहले लेफ्ट सरकार पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। दस साल की सत्ता के बाद एंटी-इंकंबेंसी का माहौल बनना स्वाभाविक है। इसके साथ ही बीजेपी और आरएसएस का धीरे-धीरे बढ़ता प्रभाव, इसाई और पिछड़े वर्गों में राजनीतिक ध्वनीकरण, और लेफ्ट के भीतर विचारधारा को लेकर चल रही आंतरिक बहसें नए सवाल खड़े कर रही हैं। अगर केरल भी हाथ से निकल गया, तो वाम दलों का राष्ट्रीय नक्शे पर टिके रहना मुश्किल हो सकता है। यह स्थिति सीधे उस विचारधारा के भविष्य पर सवाल खड़ा करती है जिसकी जड़ें भारत की स्वतंत्रता आंदोलनों, मजदूर संघर्षों और सामाजिक न्याय की लड़ाइयों में रही हैं। लेकिन क्या वाम

राजनीति का अंत निकट है? यह सवाल जितना गंभीर है, उतना ही जटिल भी। राजनीति में विचारधाराएं कभी खत्म नहीं होतीं। वे बदलती हैं, विकसित होती हैं, और कभी-कभी नए रूप में लौटती हैं। समस्या वाम विचारधारा की नहीं, बल्कि उसके प्रत्युत्करण और रणनीति की है। आज वाम दलों को आवश्यकता है कि वे नए नेतृत्व को सामने लाएं, युवाओं और नए सामाजिक समूहों से संवाद स्थापित करें, अपनी आर्थिक नीतियों को आधुनिक संदर्भों में प्रस्तुत करें और डिजिटल-युवा युग के साथ कदम मिलाकर चलें। यदि लेफ्ट अपनी निजी कठोरता छोड़कर अधिक व्यावहारिक और आक्रामक रणनीति अपनाए, तो यह विचारधारा पुनर्जीवित हो सकती है। भारत की राजनीति लगातार बदल रही है और इस बदलाव में वाम दलों का स्थान तभी सुरक्षित रहेगा जब वे अपने अतीत की सफलताओं से सीखकर भविष्य की राजनीति की भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। बंगाल और त्रिपुरा की हार ने उनके संगठन की कमज़ोरियों को उजागर कर दिया है, लेकिन यह उनके पुनर्निर्माण का अवसर भी हो सकता है। देश की राजनीतिक संरचना में वामपंथ की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है और सवाल यह है कि क्या यह भूमिका भविष्य में भी जारी रह पाएगी या वाम राजनीति इतिहास की किटाबों का अध्याय बनकर रह जाएगी।

आज भारत ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां सामाजिक और आर्थिक असमानताएं तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में वाम राजनीति की प्रासंगिकता कम नहीं हुई, बल्कि उसकी जरूरत पहले से अधिक महसूस हो रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस विचारधारा को नए भारत की नई भाषा में खुद को व्यक्त करना होगा। यही इस विचारधारा की असली परीक्षा है। और शायद यही उसका नया आरंभ भी।

एक वर्दी, तीन सेनाएँ और पूरा पाकिस्तान असीम मुनीर के सुप्रीम कमांड का नया युग

@ सौम्या चौबे

पाकिस्तान इन दिनों एक ऐतिहासिक और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार ने हाल ही में फील्ड मार्शल बनाए गए जनरल असीम मुनीर को औपचारिक रूप से देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस (CDF) नियुक्त कर दिया है। यह सिर्फ एक प्रमोशन नहीं था, बल्कि पाकिस्तान की सत्ता संरचना को पूरी तरह बदल देने वाला कदम था। अब मुनीर न सिर्फ थलसेना, बल्कि नौसेना और वायुसेना तीनों के सर्वोच्च सेनापति बन चुके हैं। पांच साल के कार्यकाल वाला यह पद पाकिस्तान के इतिहास में बनाया गया सबसे शक्तिशाली सैन्य चेहरा है। यह कहानी सिर्फ एक प्रमोशन की नहीं, बल्कि उस सत्ता-खेल की है जिसने पाकिस्तान की राजनीति, सेना, संविधान और भविष्य सबके सामने बढ़े सवाल खड़े कर दिए हैं।

संविधान बदलाफिर व्यवस्था बदली

पाकिस्तान में 1973 के बाद यह 27वाँ संवैधानिक संशोधन है। इसी संशोधन के जरिए CDF का नया पद जन्मा यह पोस्ट सेना को एक साथ तीनों सेनाओं पर नियंत्रण देती है, साथ ही नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड (NSC) की निगरानी का अधिकार भी यानी परमाणु हथियार, मिसाइल सिस्टम, न्यूक्लियर बटन, सबकुछ अब असीम मुनीर के हाथ में है। यहीं नहीं, फील्ड मार्शल होने के नाते उन्हें ऐसी कानूनी सुरक्षा मिली है जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति के समान है। उन पर आजीवन कोई जांच, मुकदमा या अभियोग नहीं चल सकता। यह पाकिस्तान की राजनीति में सैन्य शक्ति के लिए सबसे बड़ा दरवाजा खोलने जैसा था। फील्ड मार्शल बनने के बाद मुनीर ने खुद को किसके ऊपर रखा?

विशेष प्रावधानों की वजह से मुनीर अब प्रधानमंत्री से ऊपर, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर, संसद के फैसलों पर प्रभाव डालने की स्थिति में। और देश की सैन्य-सुरक्षा नीति के एकमात्र निर्णायक बन गए हैं। पाकिस्तान में इससे पहले सिर्फ जनरल अंगूठ खान ने फील्ड मार्शल की पदवी पाई थी। अब असीम मुनीर इस सूची में दूसरा नाम है। लेकिन कहीं ज्यादा शक्तियों के साथ।

असीम मुनीर की नियुक्ति से पहले व्याहुआ?

CDF की नियुक्ति से कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान में अचानक तनाव फैल गया। रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद इमरान खान को प्रताड़ित किए जाने की खबरों से अफवाह उड़ गई कि उनकी मौत हो गई है। यह सुनते ही तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के हजारों समर्थक रावलपिंडी की ओर कूच कर गए। जेल प्रशासन ने हालात बिगड़ा देख इमरान की बहन को उनसे मिलने भेजा और तब जाकर भीड़ शांत हुई। वहीं अंदर से इमरान खान ने असीम मुनीर पर तीखा हमला बोला, आरोप लगाए, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। असीम मुनीर CDF बनते ही इतने ताकतवर हो गए कि सेना ने उनके खिलाफ



बोलने वाले इमरान को राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा तक बता दिया। पाक सेना के प्रवक्ता जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सख्त चेतावनी दी कि सेना के खिलाफ किसी को भी लोगों को भड़काने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यह बयान बताता है कि पाकिस्तान में सत्ता का असली केंद्र कहाँ खिसक रहा है।

UN ने बाला गलत, अमेरिका विजय

मुनीर के प्रमोशन और शक्तियों के विस्तार पर न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में चर्चा छिड़ी। संयुक्त राष्ट्र (UN) ने इसे पाकिस्तान के लिए गलत कदम बताया। अमेरिका ने खामोशी बरतना ही बेहतर समझा। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों ने इसे खतरे की घंटी घोषित किया। वहीं, एयरफोर्स और नेवी के भीतर असंतोष की खबरें सामने आईं। क्योंकि अब सब कुछ एक ही वर्दी में सिमट चुका है।

CDF पद का मतलब क्या है?

यह पद पाकिस्तान को एक नए सैन्य ढांचे की ओर ले जाता है। तीनों सेनाएँ अब उन्हीं के आदेश पर चलेंगी। NSC और परमाणु हथियारों का कंट्रोल मिसाइल कार्यक्रम, ड्रोन सिस्टम और सुरक्षा रणनीतियों की कमान रक्षा बजट पर भी निर्णायक प्रभाव राष्ट्रपति जैसी कानूनी सुरक्षा। आजीवन किसी जांच से इम्युनिटी सीधे शब्दों में पाकिस्तान का सैन्य ढांचा अब एक शख्स की मुद्री में है।

क्या पाकिस्तान में फिर लोटेगा मिलिट्री राज?

यह सवाल आज हर विश्लेषक पूछ रहा है। पाकिस्तान

1947 से अब तक सैन्य और नागरिक शासन के बीच झूलता रहा है। अंगूठ खान, याहांखान, जिया-उल-हक और परवेज़ मुशर्रफ ये सभी सेना द्वारा सत्ता हथियाने के उदाहरण रहे हैं। अब जब संविधान में बदलाव कर सेना को स्थायी वर्चस्व मिल गया है, तो खतरा और भी बढ़ गया है। अंगूठ खान की रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि यह संशोधन पाकिस्तान के लोकतंत्र के लिए लंबे समय में घातक सावित होगा। यह बात उन लोगों द्वारा कही जा रही है जो पाकिस्तान की राजनीति को अंदर से समझते हैं।

पड़ोसियों पर क्या होगा असर?

CDF बनने के बाद पाकिस्तान में तीन प्रमुख खतरे बढ़ रहे हैं। पहला है न्यूक्लियर मिसकैलकूलेशन का खतरा। जब परमाणु कमान एक व्यक्ति पर टिकी हो, तो गलती की संभावना भी अधिक होती है। भारत और अफगानिस्तान के साथ तनाव बढ़ सकता है। दूसरा है नेवी और एयरफोर्स में असंतोष। थलसेना पर आधारित नेतृत्व की वजह से दोनों सेनाओं में असहजता है। यह प्रणाली में दरारें पैदा कर सकता है। तीसरा है लोकतंत्र कमज़ोर, आर्थिक संकट गहरा। आर्थिक रूप से लड़खड़ा रहा पाकिस्तान पहले ही IMF के कर्ज तले दबा है। अब सेना की बढ़ी ताकत राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार को बढ़ा सकती है।

क्या शहबाज़ सरकार की कुर्सी टिलेगी?

सवाल यही है कि जब सेना इतनी ताकतवर हो जाए, तो क्या लोकतंत्रिक सरकार सुरक्षित रह सकती है? शहबाज़ शरीफ की सरकार ने यह संशोधन पास करके

एक तरह से खुद अपनी ही शक्ति काट दी है। अब वही डर वापस लौट रहा है। क्या सत्ता फिर से सेना के हाथों में जाएगी? क्या पाकिस्तान एक बार फिर तख्तापलट की दहलीज पर है? इतिहास कहता है कि पाकिस्तान में एक बार जब सेना मजबूत होती है, तो राजनीतिक नेतृत्व कमज़ोर पड़ जाता है।

पाकिस्तान में सत्ता का नया समीकरण

असीम मुनीर अब, सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख, CDF, NSC के सुप्रीम हेड, परमाणु हथियारों के कंट्रोलर और फील्ड मार्शल, सभी भूमिकाएँ एक-साथ निभा रहे हैं। यह पद और शक्ति किसी भी नागरिक शासन से ऊपर है। यह एक तरह से पाकिस्तान के लिए एक वर्दी का युग शुरू होने जैसा है।

पाकिस्तान का भविष्य किस दिशा में?

असीम मुनीर की बढ़ती शक्तियाँ पाकिस्तान की राजनीति, सुरक्षा व्यवस्था और लोकतंत्र तीनों के लिए निर्णायक सावित होंगी। लेकिन यह शक्ति कितनी स्थायी होगी और इसका देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह आने वाले कुछ साल तय करेंगे। यह बात मानने में कोई संदेह नहीं कि पाकिस्तान आज ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ सत्ता का पूरा संतुलन बदल चुका है। एक व्यक्ति असीम मुनीर, अब पाकिस्तान के इतिहास में सबसे ताकतवर सैन्य अधिकारी बन चुके हैं। उनका हर फैसला देश के भविष्य, पड़ोसी देशों की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर सीधा असर डालेगा। आने वाले समय में दुनिया की निगाहें पाकिस्तान पर होंगी।

लोकसभा में बहस की चुनौती से गूंजा सदन

राहुल गांधी बनाम अमित शाह, चुनाव सुधारोंपर खुली बहस की चुनौती से गूंजा सदन

@ मनीष पांडेय

दिश्वली की सर्द सुबह में जब लोकसभा का सत्र शुरू हुआ, कोई नहीं जानता था कि यह दिन भारतीय राजनीति की एक और तीखी बहस का गवाह बनने वाला है। एजेंडा था चुनाव सुधारों पर चर्चा। लेकिन कुछ ही मिनटों में सदन का माहौल सामान्य बहस से बदलकर आरोप-प्रत्यारोप, चुनौती और जवाबी चुनौती का अखाड़ा बन गया। बहस के केंद्र में दो चेहरे थे विषयक के नेता राहुल गांधी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह।

अमित शाह का तंज और राहुल गांधी का बीच में टोकना

चर्चा के दौरान जब अमित शाह अपनी बात रख रहे थे, उन्होंने राहुल गांधी की हाल ही की तीन प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मैं राहुल गांधी के तीनों कॉन्फ्रेंस का जवाब दूँगा। एक सादी वाली, एक एटम बम वाली और एक हाइड्रोजन बम वाली हर साल का जवाब दूँगा।

यह टिप्पणी सुनते ही राहुल गांधी अपनी सीट से उठे और बीच में बोल पड़े। उन्होंने सीधे गृह मंत्री को बहस की खुली चुनौती दे दी। सदन में अचानक एक हलचल-सी दौड़ गई—मीजें थपथपाई गईं, कुछ सदस्यों ने हंसी उड़ाई, कुछ ने विरोध किया। माहौल एकदम गर्म हो चुका था।

“मेरे बोलने का क्रम मैं तय करूँगा”

राहुल गांधी के बीच में बोलने पर अमित शाह ने अपने पुराने संसदीय अनुभव की ओर इशारा करते हुए कहा कि मैं 30 साल से संसद या विधानसभा में चुनकर आ रहा हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे बोलने का क्रम मैं तय करूँगा, आप नहीं।

गृह मंत्री की इस बात ने सदन का वातावरण और ज्यादा गंभीर बना दिया। विषयकी तरफ से शोर बढ़ा तो राहुल गांधी ने दो टूक कहा कि ये डरा हुआ, घबराया हुआ रेस्पॉन्स है, सच्चा रेस्पॉन्स नहीं।

उनकी इस टिप्पणी पर अमित शाह मुस्कुराएं और बोले मैं उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ देख रहा हूँ। मैं क्या बोलूँगा वह मैं तय करूँगा, उनके उकसावे में नहीं आऊंगा। सदन में बैठे सांसदों को लग चुका था कि आज की चर्चा अब सिर्फ चुनाव सुधारों तक सीमित नहीं रहने वाली।

“अमित शाह जी, बहस की जिए”

जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तो राहुल गांधी ने अपनी चुनौती दोहराई। उन्होंने कहा कि कल मेरा सवाल था कि इतिहास में पहली बार चुनाव आयुक्त को फुल इम्बूनिटी दी गई है। मैं इसके पीछे का कारण जानना चाहता था।

दूसरा, हरियाणा में 19 लाख फर्जी मतदाताओं का मुद्दा है। अमित शाह जी ने सिर्फ एक उदाहरण लिया। चलिए, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बहस कर लेते हैं। यह बहुत अच्छा विचार है। अमित शाह जी, मैं आपको खुली बहस की चुनौती देता हूँ। उनकी आवाज में आत्मविश्वास था और चुनौती सीधे गृह मंत्री को दी गई थी। कुछ क्षणों के लिए



सदन में एक गहरी चुप्पी छा गई—हर कोई यह देखने का इंतजार कर रहा था कि शाह क्या जवाब देंगे।

“जवाब दूँगा, लेकिन अपने क्रम से”

अमित शाह ने अपनी शैली में शांत होकर कहा कि अध्यक्ष महोदय, उन्हें मेरे जवाब सुनने के लिए थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। मैं हर बात का जवाब दूँगा, लेकिन मेरे भाषण का क्रम वे तय नहीं करेंगे। वह मैं ही तय करूँगा।

इसके बाद शाह ने विषयक द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आरोप नए नहीं हैं और कांग्रेस के शासन काल में भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं। उन्होंने विशेष रूप से जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के दौर का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के एक पुराने मामले का हवाला भी दिया, जिसमें यह कहा गया था कि सोनिया गांधी भारतीय नागरिक बनने से पहले ही मतदाता सूची में शामिल हो गई थीं।

“जब हम हारे, तब मतदाता सूची ठीक थी”

अपनी बात जारी रखते हुए गृह मंत्री ने विषय पर तंज कसते हुए कहा कि हम 2018 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हारे। कर्नाटक में भी 2014 के बाद हारे। तेलंगाना, तमिलनाडु, बंगाल कई जगह हम जीते नहीं। तब तो यह मतदाता सूची बहुत अच्छी होती है। तब तो आप नए कपड़े पहनकर शपथ ले लेते हैं।

उनकी इस टिप्पणी पर सदन में जोरदार हँसी गूंज उठी। बीजेपी सांसद में जैसे थपथपाने लगे और विषयक ने इसका विरोध किया। लेकिन शाह अपनी लाइन पर टिके रहे। उनका कहना था कि विषय मतदाता सूची को केवल तब गलत कहता है, जब उसे चुनावी परिणाम अपने पक्ष में नहीं मिलते।

बहस की मांग या राजनीतिक रणनीति?

राहुल गांधी द्वारा दी गई खुली बहस की चुनौती को कई राजनीतिक विश्लेषक अलग-अलग नज़रों से देख रहे हैं। कुछ का मानना है कि राहुल गांधी इस समय विषय के एक आक्रामक नेता की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं, और लोकसभा में उनका यह हस्तक्षेप उसी रणनीति का हिस्सा है दूसरी ओर, अमित शाह की प्रतिक्रिया उनके राजनीतिक अनुभव का परिचय देती है वे चुनौती को स्वीकार करते हुए भी अपने नियमों और प्रक्रिया को नज़र आंदोज नहीं करते। उन्होंने राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने का आश्वासन तो दिया, लेकिन उनके दबाव में आने से इनकार किया।

चुनाव सुधारों की बहस कहाँ खो गई?

इस पूरे घटनाक्रम के बीच असली मुद्दा—चुनाव सुधार कुछ समय के लिए पीछे छूट गया। यह बहस चुनाव आयुक्त की इम्बूनिटी, मतदाता सूची की विश्वसनीयता, फर्जी मतदाताओं और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता जैसे

विषयों पर केंद्रित थी लेकिन सदन में जो हुआ, वह इस बात का संकेत है कि आगामी चुनावों से पहले राजनीति का तापमान कितना बढ़ने वाला है। दोनों पक्ष अपनी-अपनी कथा को जनता तक पहुंचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और संसद वह मंच बन गई है जहाँ यह संघर्ष सबसे ज्यादा साफ दिखाई देता है।

राहुल गांधी की चुनौती एक टीवी बहस

संसद में हुई इस तीखी नोकझोंक का असर आने वाले दिनों की राजनीतिक चर्चाओं पर जरूर पड़ेगा। क्या राहुल गांधी की चुनौती एक टीवी बहस की तरह जमीन पर उत्तर पाएगी? क्या अमित शाह वास्तव में इन आरोपों का विस्तृत जवाब सदन में देंगे? और क्या चुनाव सुधारों पर कोई ठोस सहमति बन पाएगी? इन सवालों के जवाब अभी बाकी हैं। लेकिन इतना तो तय है कि 10 दिसंबर का यह सत्र आने वाली कई बहसों की भूमिका तैयार कर गया है।

राहुल गांधी की आक्रामक चुनौती

लोकसभा का यह दिन भारतीय लोकतंत्र की उस जीवंतता का उदाहरण था जहाँ बहसें सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि वास्तविक टकराव, सवाल, जवाब और चुनौती के रूप में दिखाई देती हैं। राहुल गांधी की आक्रामक चुनौती और अमित शाह का आत्मविश्वास था और विषयक नेता की विश्वसनीयता, फर्जी मतदाताओं और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता जैसे

जननी के प्रति

भेदभाव के इन कठिन दिनों में
प्रकृति ने मुझे बचाए रखा है

जब भी दुपट्टे की भार से मन उजबुजाया
तब हल्की रुवा ने उसे सरकाया है

मुझे बचाया है
वहीं जिसने मुझे जना है

जब-जब किसी सरकारी बबुली ने
रोजगार के बारे में पूछा मुझे

एक गहरी खाई के उस पार से
तब भी मुझे प्रकृति ने ही बचाया है

बारिश शुरू हो जाती है
और खाई के इस पार

उस पार
दोनों पार बराबर बरसती है

संभव हो कि उनके पास छतरी हो
और वह खुद को खुशनसीब मल्सूस करें

पर मेरे लिए यह दुःख की बात होगी
सभी जगहों पर अनामंत्रित मैंने खुद को

खुले आसमान में तारों के बीच आमंत्रित पाया है
जब बारिश होती है तो असमानता की सभी तकीरें

बहकर एक ही समुद्र में ले जाती हैं
प्रतियोगिता के बीच दबी नैं जब खुद से लारी हूँ

तब तब मृत्यु आसान जान पड़ी है पर
गंगा में डूबता सूरज देखने के लोभ से मैं ज़िंदा हूँ

मुझे गंगा ने, सूरज ने, हवाओं ने ही ज़िंदा रखा है
भेद-भाव से ऊँच-नीच से

जब भी असमानता को जानने की इच्छा से
प्रेम और मोह को समझने की इच्छा से

मैं वेद-पुराणों की तरफ मुड़ी
उनकी धर्म आपदधर्म की बातों ने

किंतु परंतु
यद्यपि तथापि ने

मुझे और उलझाया है
तब प्रकृति ने मुझे बचाया है

वहीं जिसने मुझे जना है
अपने से हारकर जब भी मैंने

आँखें बंद कर मृत्यु को मनसूस करना चाहा है
तब सूरज की किरणों ने ही तो

जगाया है
बचाया है



उभरे पेट और पीली आँखों वाले बच्चे
स्टेशन पर दौड़ते हुए

फिर भी विद्रोह तो दूर
मैंने प्रार्थना भी नहीं की

जब अवानक ही मुझसे टकरा जाते
तब ब्रह्मांड का पूरा दुःख एक साथ

पड़ोस की एक जवान लड़की
रोती-हँफती

मुझसे टकरा जाता है
पर इतना दुःख भी काफ़ी नहीं है

हरी-थकी
यागल हो रही है धीरे-धीरे

मैं नज़रें फिराए निकल जाती हूँ वर्लैं से
स्टेशन के पिछले इलाके में

फिर भी
नहीं है इतनी हिम्मत

बहुत पुराना एक बरगद का पेड़
कट रहा है

कि उसे कहूँ
भाग जा! भाग जा!

काठा जा रहा है
मशीनों से

अपने प्रेमी के साथ दूर
बहुत दूर

उसे कटते देख गले में यानी अटकने
जैसा कट्ट लेता है

उमा भगत
नई यीढ़ी की कवि

मौन

रुपये की कमज़ोरी

आम आदमी की जेब ढीली, सपने महंगे

गिरावट की शुरुआत: डॉलर के आगे रुपये का सा जाना

भा श्वेत रुपये की कीमत अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगातार गिर रही है, और दिसंबर 2025 तक यह 90 के पार चली गई है। 6 दिसंबर को यह लगभग 89.95 से 90.43 रुपये प्रति डॉलर के आसपास घूम रही थी, जो एक रिकॉर्ड निचला स्तर है। यह गिरावट साल भर में 5 प्रतिशत से ज्यादा की है, जो एशिया की अन्य मुद्राओं में सबसे ज्यादा है। मुख्य वजहें अमेरिका की तरफ से भारत पर 50 प्रतिशत तक के टैरिफ लगाना, विदेशी निवेश का बाहर जाना और व्यापार की अनिश्चितताएं हैं। अगर हम पीछे देखें, तो 2024 के अंत में यह 85 रुपये के आसपास था, लेकिन 2025 में वैश्विक दबाव ने इसे तेजी से नीचे धकेल दिया। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर यही सिलसिला चला तो 2026 के अंत तक यह 91 तक पहुंच सकती है। यह सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं, बल्कि आम लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डाल रही है। घर से लेकर बाजार तक, हर चीज महंगी हो रही है। लेकिन एक तरफ यह निर्यातकों के लिए फायदा भी ला रही है, क्योंकि भारतीय सामान विदेश में सस्ता पड़ रहा है। फिर भी, आयात पर निर्भर भारत के लिए यह चिंता की बात है। तेल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे आयात महंगे होने से महंगाई बढ़ रही है, जो गरीब और मध्यम वर्ग को सबसे ज्यादा साताती है। सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) इस पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन बाजार की ताकतों को खुद संभालने का मौका दे रहे हैं। कुल मिलाकर, यह गिरावट एक संकेत है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के बदलाव भारत को कैसे छू रहे हैं। आम आदमी सोच रहा है कि कब तक यह बोझ सहना पड़ेगा, और क्या कोई राहत मिलेगी। यह सवाल सिर्फ अर्थशास्त्रियों का नहीं, बल्कि हर घर का है।

घर के बजट पर संकेत: रोजगार की चीजें चाहों दौरी महंगी

रुपये की कमज़ोरी से सबसे पहले घरेलू खर्चों पर असर पड़ रहा है, क्योंकि भारत तेल, सोना और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कई सामान आयात करता है। दिसंबर 2025 में पेट्रोल-डीजल की कीमतें 3-5 रुपये प्रति लीटर बढ़ चुकी हैं, क्योंकि कच्चा तेल डॉलर में खरीदा जाता है। एक सामान्य परिवार जो महीने में 5000 रुपये का ईंधन खर्च करता है, अब 200-300 रुपये ज्यादा दे रहा है। किराने का सामान भी महंगा हो गया है, क्योंकि दालें, तेल और सब्जियां विदेश से आने वाली चीजों पर निर्भर हैं। महंगाई दर 6 प्रतिशत के पार पहुंच गई है, जो पिछले साल से 1.5 प्रतिशत ज्यादा है। मोबाइल फोन या टीवी खरीदना अब पहले से 5-7 प्रतिशत महंगा पड़ रहा है, क्योंकि इनके पार्ट्स चीन और अमेरिका से आते हैं। मध्यम वर्ग के लोग



जो पहले सालाना 50,000 रुपये का इलेक्ट्रॉनिक्स बजट रखते थे, अब 53,000-55,000 रुपये खर्च कर रहे हैं। सोने की कीमतें भी 10 प्रतिशत चढ़ गई हैं, जो शहदियों के मौसम में परिवारों को परेशान कर रही हैं। लेकिन एक सकारात्मक पक्ष यह है कि रेमिटेंस भेजने वाले प्रवासी भारतीयों के परिवारों को फायदा हो रहा है। अगर कोई विदेश से 1000 डॉलर भेजता है, तो अब यह 90,000 रुपये बन जाता है, पहले 85,000 था। फिर भी, कुल मिलाकर नुकसान ज्यादा लग रहा है। विशेषज्ञ कहते हैं कि यह चक्रवृद्धि प्रभाव पैदा कर रहा है, जहां एक चीज महंगी होने से दूसरी भी प्रभावित होती है। गरीब परिवार जो पहले से ही तंग हैं, अब और मुश्किल में फंस गए हैं। सरकार सब्सिडी बढ़ाने की बात कर रही है, लेकिन तत्काल राहत कम है। यह स्थिति सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी अर्थव्यवस्था आयात पर कम निर्भर हो सकती है। स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देकर शायद यह बोझ कम हो। लेकिन फिलहाल, हर महीने के अंत में आने वाला बिल आम आदमी को चुभ रहा है।

विदेशी डिवी का सपना: पदार्थ का खर्चावर्ती चढ़ा आसमान पर

विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए रुपये की गिरावट एक बड़ा झटका साबित हो रही है। 2025 में अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जाने वाले छात्रों का सालाना खर्च 5-10 लाख रुपये बढ़ गया है। उदाहरण के लिए, एक अमेरिकी यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस 30,000 डॉलर है, जो पहले 25 लाख रुपये पड़ती थी, अब 27 लाख हो गई है। रहने-खाने का खर्च भी 15,000 डॉलर सालाना, जो 13 लाख से बढ़कर 13.5 लाख रुपये हो गया। मध्यम वर्ग के परिवार जो शिक्षा लोन लेते हैं, अब ब्याज समेत चुकाने का बोझ दोगुना महसूस कर रहे हैं। एक छात्र जिसने 2024 में लोन लिया था, अब मूल राशि ही 10-15 प्रतिशत ज्यादा चुकानी पड़ रही है। कनाडा में एमबीए करने वाली नेहा कहती है, “मेरी फीस हर सेमेस्टर 2 लाख ज्यादा हो गई, पापा को अतिरिक्त नौकरी करनी पड़ रही है।” ऐसे में कई छात्र भारत या एशियाई देशों की ओर रुख कर रहे हैं, जहां खर्च कम है। लेकिन गुणवत्ता की

चिंता बनी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह गिरावट लंबे समय में छात्रों के करियर को प्रभावित करेगी, क्योंकि अच्छी जॉब के लिए विदेशी डिग्री जरूरी मानी जाती है। फिर भी, कुछ सकारात्मक पहलू हैं। अगर छात्र विदेश जाकर नौकरी पा लें, तो कमज़ोर रुपये से उनकी कमाई ज्यादा मूल्यवान हो जाएगी। भारत सरकार स्कॉलरशिप बढ़ा रही है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं। कुल 1.5 लाख छात्र हर साल विदेश जाते हैं, और इस साल 20 प्रतिशत कम हो गए हैं गिरावट की वजह से। यह सोचने लायक है कि क्या शिक्षा का सपना सिर्फ अमीरों का हो रहा है। माता-पिता साल भर की मेहनत एक सेमेस्टर की फीस में उड़ते देख रहे हैं। शायद समय आ गया है कि हम घरेलू संस्थानों को मजबूत करें, ताकि हर बच्चे को बाबार मौका मिले।

बड़ी तरवीर: फायदे-नुकसान और सरकार की रणनीति

रुपये की गिरावट का असर सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। एक तरफ नियांत बढ़ रहा है, क्योंकि आईटी और फार्मा कंपनियां विदेश में सस्ते दामों पर सामान बेच पा रही हैं। 2025 में नियांत 4 प्रतिशत ऊपर गया है। लेकिन आयात महंगे होने से कंपनियों का उत्पादन खर्च बढ़ा है, जो उपभोक्ताओं तक पहुंच रहा है। महंगाई नियंत्रण में रहने से आरबीआई को सतर्क रहना पड़ रहा है। दिसंबर में आरबीआई ने 1 लाख करोड़ रुपये का ओपन मार्केट ऑपरेशन (ओएमओ) खरीद घोषित किया, ताकि बाजार में नकदी आए और रुपये को सहारा मिले। साथ ही, 5 अरब डॉलर का फॉरेक्स स्वैप किया गया, जो विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करेगा। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कहते हैं कि रुपये पर घरबरहट की जरूरत नहीं, यह अगले साल संभल जाएगी। लेकिन आम लोगों के लिए यह इंतजार लंबा लग रहा है। छोटे व्यवसायी जो कच्चा माल आयात करते हैं, अब लाभ मार्जिन घटा रहे हैं। पर्यटन केंद्र में विदेशी पर्यटक बढ़े हैं, लेकिन भारतीयों का विदेश घूमना कम हो गया। कुल मिलाकर, यह संतुलन की बात है। कमज़ोर रुपये से कुछ सेक्टर चमक रहे हैं, लेकिन बहुसंख्यक आबादी पर दबाव है। सरकार आयात शुल्क कम करने और स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहन देने की योजना बना रही है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि परिवार बजट बनाएं, बचत बढ़ाएं और डॉलर-आधारित निवेश से बचें। भविष्य में अगर अमेरिका के टैरिफ हों, तो राहत मिल सकती है। यह समय आत्मनिर्भरता का है, जहां हम अपनी ताकत पर भरोसा करें। गिरावट एक चुनौती है, लेकिन इससे सीख लेकर मजबूत बन सकते हैं। क्या हम इस मौके को हलचल में बदल देंगे? यह सवाल हर नागरिक के सामने है।

काम के बाद भी काम का बोझ

राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025 क्यों बन गया ज़रूरत?

@ आनंद मीणा

आज का समय तेज़ है बहुत तेज़। एक उंगली में पूरा दफ्तर समाया हुआ है। मोबाइल फोन जेव में है, लेकिन काम दिमाग में 24 घंटे धूमता रहता है। पहले दफ्तर की घंटी बजती थी और काम खत्म हो जाता था, अब व्हाट्सएप की घंटी बजती है और काम फिर शुरू हो जाता है। देर रात बॉस का मैसेज, छुट्टी के दिन ज़रूरी ईमेल, परिवार के साथ बैठे-बैठे अचानक मीटिंग-आज का कर्मचारी कभी पूरी तरह ऑफ इयूटी हो ही नहीं पाता।

इसी बदलती और थकाने वाली कार्य-प्रणाली को देखकर संसद में एक अहम पहल हुई है। इसका नाम है राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025। यह बिल लोकसभा सांसद सुप्रिया सुलो द्वारा पेश किया गया है। इस बिल का मकसद साफ़ है- कर्मचारियों को यह कानूनी अधिकार देना कि वे काम के तथा समय के बाद दफ्तर से डिस्कनेक्ट हो सकें, बिना किसी डर के।

काम और निजी जीवन के बीच मिटती हुई रेखा, एक समय होता था जब दफ्तर से घर आने का मतलब होता था- अब आराम। अब हालात बिल्कुल उलट हैं। घर ही दफ्तर बन चुका है। मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट ने काम को आसान तो बनाया, लेकिन आराम को मुश्किल कर दिया रिमोट वर्क, वर्क फ्रॉम होम और डिजिटल टूल्स के दौर में कर्मचारियों से यह उम्मीद कर ली गई है कि वे हर समय ऑनलाइन उपलब्ध रहें। छुट्टी का दिन हो या रात के 11 बजे बस एक छोटा सा काम है! कहकर मैसेज आ ही जाता है। धीरे-धीरे यह आदत बन गई, और अब यह दबाव बन चुकी है। इस लगातार जुड़े रहने की मजबूरी ने कर्मचारियों की मानसिक सेहत पर गहरा असर डाला है। नींद खराब हो रही है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, परिवार से दूरी हो रही है और वर्क-लाइफ बैलेंस नाम की चीज़ सिर्फ़ किताबों में रह गई है।

क्यों ज़रूरी हो गया राइट टू डिस्कनेक्ट कानून?

भारत का वर्कफोर्स तेज़ी से बदल रहा है। आईटी सेक्टर, मीडिया, कॉरपोरेट दुनिया, स्टार्टअप्स हर जगह काम के घंटे अब सिर्फ़ 9 से 6 तक सीमित नहीं रहे। काम दिन में भी चलता है और रात में भी इसका सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि कर्मचारियों को यह महसूस होने लगा कि वे कभी भी पूरी तरह फ्री नहीं हैं। शरीर घर पर होता है, लेकिन दिमाग दफ्तर में अटका रहता है। यही स्थिति धीरे-धीरे तनाव, अवसाद और बर्नआउट जैसी समस्याओं को जन्म दे रही है। इसी बढ़ती चिंता को देखते हुए यह बिल लाया गया है। इसका उद्देश्य किसी कंपनी के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ कार्य-संस्कृति बनाना है, जहां कर्मचारी काम भी करें और ज़िंदगी भी जी सकें।

राइट टू डिस्कनेक्ट बिल क्या कहता है

इस बिल का सीधा-सा मतलब यह है कि कर्मचारी



को यह अधिकार होगा कि वह ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद काम से जुड़े कॉल, मैसेज और ईमेल का जवाब देने के लिए बाध्य न हो। यानी दफ्तर का समय खत्म मतलब काम खत्म कोई दबाव नहीं कोई डर नहीं कोई ज़बरदस्ती नहीं।

कंपनी यह उम्मीद नहीं कर सकेगी कि कर्मचारी हर समय उपलब्ध रहे। अगर कर्मचारी चाहे तो मोबाइल स्विच ऑफ कर सकता है, ईमेल का जवाब अगले दिन दे सकता है और बिना किसी अपराधबोध के अपने परिवार या अपने लिए समय निकाल सकता है।

इमरजेंसी में संपर्क की छूट, लेकिन मजबूरी नहीं

बिल यह भी समझता है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं जहां कंपनी को तुरंत संपर्क करना पड़े। इसलिए इसमें यह प्रावधान भी रखा गया है कि इमरजेंसी की स्थिति में मालिक कर्मचारी से काम के बाद संपर्क कर सकता है।

लेकिन यहां सबसे अहम बात यह है कि कर्मचारी उस कॉल या मैसेज का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं होगा। अगर वह अपनी मर्जी से जवाब देता है, तो वह उसकी इच्छा होगी, मजबूरी नहीं।

ओवरटाइम का कानूनी अधिकार

अक्सर देखा जाता है कि कर्मचारी काम के बाद भी घंटों काम करता रहता है, लेकिन उसका कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं मिलता। यह बिल इस अन्याय को भी खत्म करने की कोशिश करता है। अगर कोई कर्मचारी अपनी सहमति से ऑफिस टाइम के बाद काम करता है, कॉल उठाता है या ईमेल का जवाब देता है, तो कंपनी को उसे स्टैंडर्ड ओवरटाइम वेतन देना अनिवार्य होगा। इससे

कर्मचारियों को उनके समय की सही कीमत मिलेगी।

अनुशासनात्मक कार्रवाई से सुरक्षा

इस बिल की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यह कर्मचारियों को कानूनी सुरक्षा देता है। अभी तक बहुत से कर्मचारी डर के कारण रात के मैसेज का जवाब देते हैं- उन्हें डर रहता है कि कहीं बॉस नाराज़ न हो जाए, प्रमोशन न रुक जाए या नौकरी ही न चलती जाए।

लेकिन अब अगर कोई कर्मचारी काम के बाद कॉल नहीं उठाता या मैसेज का जवाब नहीं देता, तो कंपनी उसके खिलाफ, स्पेंशन, टर्मिनेशन, वेतन कटौती या किसी भी तरह की सज़ा नहीं दे सकेगी। यह पूरी तरह गैर-कानूनी माना जाएगा।

नियम तोड़ने वाली कंपनियों पर ज़ुमानि

सिर्फ़ कानून बना देने से बात पूरी नहीं होती, जब तक उसके डर का पालन न हो। इसलिए इस बिल में सख्त पेनल्टी का भी प्रावधान रखा गया है। अगर कोई कंपनी इस नियम का उल्लंघन करती हुई पाई जाती है, तो उस पर उसके कुल कर्मचारी वेतन के 1% के बराबर जुर्माना लगाया जा सकता है। यह रकम बड़ी कंपनियों के हल्के करोड़ों तक पहुंच सकती है, जिससे वे नियमों को हल्के में नहीं ले सकेंगी।

कर्मचारियों की ज़िंदगी में व्याबदलेगा

अगर यह बिल कानून बनता है, तो इसका सीधा असर लाखों कर्मचारियों की ज़िंदगी पर पड़ेगा। वे बिना डर के अपना फोन स्विच ऑफ कर सकेंगे। परिवार के साथ समय बिता सकेंगे। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। नींद बेहतर होगी। रिश्तों में सुधार होगा। और काम के प्रति नियम उत्साह लौटेगा। जब इसान मानसिक रूप से ताजा रहता होगा।

है, तभी वह बेहतर काम कर पाता है। थका हुआ दिमाग कभी भी रचनात्मक और उत्पादक नहीं हो सकता।

व्याकुंपनियों को होगा नुकसान?

कुछ लोग यह सवाल भी उठाते हैं कि इस तरह के कानून से कंपनियों का काम प्रभावित हो सकता है। लेकिन दुनिया के कई देशों में ऐसा कानून पहले से पौँजूद है। वहां इससे न तो कारोबार रुक और न ही विकास थमा। उल्या, कर्मचारियों की कार्यक्षमता और निष्ठा में बढ़ोतरी हुई। दरअसल, जब कर्मचारी खुश और संतुलित होता है, तो वह कंपनी के लिए ज़्यादा ईमानदारी और मन से काम करता है। तनाव में किया गया काम सिर्फ़ मजबूरी होता है, समर्पण नहीं।

ज़िंदगी भी ज़रूरी है!

राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025 सिर्फ़ एक कानून नहीं है, बल्कि यह सोच बदलने की शुरुआत है। यह संदेश देता है कि कर्मचारी मशीन नहीं हैं। वह भी एक इंसान है, जिसकी अपनी ज़िंदगी, परिवार, भावनाएं और सीमाएं हैं। काम ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदगी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है।

सम्मान के साथ जीने का हक

आज जब मोबाइल ने काम और आराम के बीच की रेखा मिटा दी है, तब इस कानून की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा महसूस होती है। राइट टू डिस्कनेक्ट बिल कर्मचारियों को सिर्फ़ आराम का अधिकार नहीं देता, बल्कि उन्हें सम्मान के साथ जीने का हक देता है। अगर यह बिल पास हो जाता है, तो यह भारत के श्रम कानूनों के इतिहास में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव साबित होगा।

दुनिया की निशाहें भारत-रूस पर

@ रिकॉ विश्वकर्मा

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा बहज एक औपचारिक राजनयिक यात्रा नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे वैश्विक राजनीति का एक बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है। यही बजह है कि इस दौरे की चर्चा सिर्फ भारत या रूस तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका से लेकर यूरोप और एशिया तक हर देश की नजर नई दिल्ली पर टिकी हुई है। इस दौरे की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि तीन महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की मुलाकात चीन के तियांजिन शहर में हुई थी। दोनों नेता वहां शंघाई सहयोग संगठन यानी एसोसिओ शिखर सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। उस मुलाकात के बाद पूरी दुनिया ने एक बार फिर भारत-रूस दोस्ती की मजबूती को खुलकर देखा था। अब जब पुतिन दोबारा भारत आ रहे हैं, तो यह यात्रा सिर्फ पुराने रिश्तों की गर्माहट नहीं, बल्कि भविष्य की बड़ी रणनीति का संकेत भी मानी जा रही है।

अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर कितनी ऊँची है भारत की उड़ान?

पुतिन एसे समय पर भारत आ रहे हैं, जब भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। बीते कुछ महीनों में भारत जिस रफ्तार से आगे बढ़ा है, उसने बड़े-बड़े देशों को भी चौका दिया है पिछले महीने वित्त मंत्रालय की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए, उनके अनुसार जुलाई से सितंबर की तीसरी तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ दर 8.2 प्रतिशत रही। इस आंकड़े ने दुनिया भर के आर्थिक विशेषज्ञों को हैरानी में डाल दिया। इससे पहले माना जा रहा था कि अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी-भरकम टैरिफ की वजह से भारत की रफ्तार धीमी हो सकती है, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा।

आज हालात यह हैं कि भारत इस साल जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत की कुल जीडीपी 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है वहीं दूसरी ओर रूस की कुल जीडीपी 2.54 ट्रिलियन डॉलर के आसपास बताई जा रही है। इस हिसाब से देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था रूस से लगभग दोगुनी हो चुकी है। रूस फिलहाल दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की सूची में नौवें स्थान पर आता है। यह बदलाव अपने आप में इस बात का संकेत है कि वैश्विक सत्ता संतुलन धीरे-धीरे नई दिशा में बढ़ रहा है।

तेल, टैरिफ और ट्रंप की सख्ती

भारत और रूस के रिश्तों का सबसे मजबूत संबंध ऊर्जा सहयोग माना जाता है, खासकर कच्चे तेल की खरीद। बीते कुछ वर्षों में भारत रूस से बड़े पैमाने पर कच्चे तेल खरीदता रहा है। इसी मुद्दे को लेकर अमेरिका और भारत के रिश्तों में कुछ तल्खी भी देखने को मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ की पेनल्टी लगा दी है। इसके अलावा 25 प्रतिशत टैरिफ पहले ही बढ़ाया जा चुका है। इस तरह भारत पर कुल 50



प्रतिशत तक का टैरिफ दबाव आ गया है ट्रंप का तर्क है कि भारत अमेरिका के मुकाबले अपने यहां ज्यादा टैरिफ लगाता है। इसलिए जबाब में अमेरिका भी सख्त कदम उठा रहा है। वहीं, रूस से तेल खरीदने को उन्होंने सीधी पेनल्टी की श्रेणी में रखा है। इसके बावजूद भारत ने न तो अपने ऊर्जा हितों से समझौता किया और न ही अपनी आर्थिक रफ्तार को कमज़ोर पड़ने दिया। यही बात इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा दिलचस्प बना देती है।

दिल्ली में होगा गर्मजारी भारत-स्वागत

रूसी राष्ट्रपति पुतिन गुरुवार शाम दिल्ली पहुंचेंगे। कृतनीतिक संकेतों के मुताबिक वे एयरपोर्ट से सीधे प्रधानमंत्री मोदी के आवास जाएंगे। वहां दोनों नेताओं के बीच निजी मुलाकात होगी और उनके सम्मान में विशेष डिनर का भी आयोजन किया गया है। इस निजी बातचीत को बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि इसमें कई ऐसे मुद्दे उठ सकते हैं जिन पर सार्वजनिक मंचों पर खुलकर बात नहीं की जाती। यह मुलाकात दोनों देशों के आपसी भरोसे और रणनीतिक साझेदारी को नई ऊर्जा दे सकती है।

ऊर्जा, व्यापार और रक्षा पर बड़े समझौते सम्भव

सूत्रों के मुताबिक इस दौरे के दौरान ऊर्जा, व्यापार और रक्षा क्षेत्र से जुड़े कई बड़े समझौते हो सकते हैं। भारत और रूस पहले से ही रक्षा क्षेत्र में लंबे समय से साझेदार रहे हैं। अब इस सहयोग को नए दौर में ले जाने की संभावना है। ऊर्जा क्षेत्र में भी दोनों देश नए दीर्घकालिक

करार कर सकते हैं, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा और मजबूत हो सके। इसके अलावा व्यापार में भी स्थानीय मुद्रा के इस्तेमाल, निवेश बढ़ाने और नई तकनीकों के आदान-प्रदान पर चर्चा हो सकती है।

राजनीति की धड़कनें हुई तेज

यह दौरा सिर्फ द्विपक्षीय स्तर तक सीमित नहीं है। इसकी गूंज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी साफ सुनाई दे रही है। अमेरिका के अलावा यूक्रेन, चीन और पाकिस्तान की नजरें भी इस मुलाकात पर टिकी हैं। यूक्रेन युद्ध के लंबे खिंचने के बाद रूस वैश्विक स्तर पर नए संतुलन बनाने की कोशिश में जुटा है। वहीं भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के तहत सभी बड़े देशों के साथ संतुलित रिश्ते बनाए रखने की रणनीति पर चल रहा है। चीन इस पूरे घटनाक्रम को बेहद बारीकी से देख रहा है, क्योंकि भारत-रूस की नजदीकियां एशियाई भू-राजनीति पर सीधा असर डालती हैं। वहीं पाकिस्तान की दिलचस्पी इस बात में है कि क्या भारत को इस दौर से सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नया फायदा मिलने वाला है या नहीं।

गई विश्व व्यवस्था में भारत की भूमिका कितनी?

आज की तारीख में भारत सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं रहा, बल्कि वह विश्व राजनीति के केंद्र में अपनी जगह बना चुका है। भारत अब निर्णय लेने वाला देश बन रहा है, न कि सिर्फ दूसरों के फैसलों का असर डोलने वाला। रूस के साथ मजबूत रिश्ते बनाए रखना सुनाई दे सकती है।

भारत की उसी रणनीति का हिस्सा है, जिसमें वह किसी एक शक्ति ब्लॉक का हिस्सा बनने के बजाय हर बड़े देश के साथ संतुलन बनाए रखना चाहता है।

क्या संदेश दे रही है यह मुलाकात?

पुतिन की यह भारत यात्रा कई संदेश देती है। भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। रूस भारत को अपना भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार मानता है। अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत अपने राष्ट्रीय हितों पर अडिग है। एशिया में शक्ति संतुलन एक बार फिर नए मोड़ पर खड़ा है। यह मुलाकात साफ संकेत देती है कि आने वाला समय बहुधीवीय विश्व का होगा, जहां भारत, रूस, चीन और अमेरिका चारों अपनी-अपनी भूमिका नए सिरे से तय करेंगे।

कई नए समीकरण गढ़ सकती हैं मुलाकातें

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यह दौरा सिर्फ एक औपचारिक राजनयिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह आने वाले सालों की वैश्विक राजनीति की इलक भी देता है। भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था, रूस के साथ बढ़ती साझेदारी और अमेरिका के साथ चल रहे टैरिफ तनाव। इन सबके बीच यह मुलाकात कई नए समीकरण गढ़ सकती हैं। दिल्ली में होने वाली बातचीत सिर्फ दो नेताओं तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि इसके फैसलों की गूंज वाशिंगटन, बीजिंग, मॉस्को और इस्लामाबाद तक सुनाई दे सकती है।



प्रभु कृपा दुर्दिवारण समाप्ति

BY

**Arihanta
Industries**

- BHRINGRAJ
- AMLA
- REETHA
- SHIKAKAI

100 ML



15 ML



**ULTIMATE
HAIR
SOLUTION**

NO ARTIFICIAL
COLOR
FRAGRANCE
CHEMICAL

KESH VARDAK SHAMPOO

The complete solution of all hair problems:

- Prevent hair fall and make hair follicle strong.
- Promote hair growth.
- Free from all artificial & harmful chemicals like., SLS.
- 100% pure ayurvedic shampoo.
- Suitable for all hair types.



ORDER ONLINE @ :

amazon

arihanta.in

Arihanta Industries